सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा में सामान्यतया प्रयुक्त शब्दावली

The Institute of Chartered Accountants of India
(Set up by an Act of Parliament)
New Delhi

सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा
में
सामान्यतया प्रयुक्त शब्दावली

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)
नई दिल्ली

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सभी अधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से इलैक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोकापी, रिकार्डिंग या अन्यथा प्रकाशक की लिखित में पूर्वानुमति के बिना पुनरूद्धत, प्रणाली में स्टोर या संप्रेषित नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण	:	2015
समिति/विभाग	:	सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा समिति
ई-मेल	:	cpf_ga@icai.in
वेबसाइट	:	www.icai.org
मूल्य	:	` 100/-
आईएसबीएन नं.	:	978-81-8441-576-6
प्रकाशक	:	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की ओर से प्रकाशन विभाग 'आईसीएआई' भवन, पो.बा. नं. 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002
मुद्रक	:	साहित्य भवन पब्लिकेशनज, हास्पीटल रोड़, आगरा-282003 जून/2015/पी 0000 (नवीन)

प्राक्कथन

गत वर्षों के दौरान सनदी लेखाकार (सी ए) के व्यवसाय (पेशे) में भारी बदलाव हुए हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) की पूर्णता, कौशल एवं ज्ञान के लिए निरन्तर खोज ने सनदी लेखाकारों को देश के व्यावसायिक जगत में एक उच्च स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया है। सनदी लेखाकार के पेशे ने वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा और अन्य निगमित क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभायी है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान अपनी सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा समिति के माध्यम से यह प्रयास करता रहा है कि सनदी लेखाकारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति हमेशा जागरूक रखा जाए और इसके लिए वह समय-समय पर विभिन्न प्रकाशन निकालता रहता है ताकि सदस्य सनदी लेखाकार सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा के क्षेत्र में पूर्णतया जागरूक व अद्यतन रहें और अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

नये सुधारों के प्रारम्भ और निरन्तर परिवर्तनशील व्यवसायिक परिवेश में समिति ने नवोन्मेष गतिविधियों के अन्तर्गत अपनी पुस्तिका 'सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखों में सामान्यतया प्रयुक्त शब्दावली' को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इससे एक सामान्य पाठक जब भी समाचार-पत्र के वित्तीय पृष्ठों और व्यवसायिक पत्रिकाओं का अध्ययन करता है, सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा की नवीन शब्दावली को समझने में सहायता प्राप्त कर सकता है।

मैं समिति के अध्यक्ष, सीए. विजय गर्ग, उपाध्यक्ष सीए. संजय अग्रवाल और सचिवालय के अन्य सदस्यों की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इन परिवर्तनशील परिस्थितयों में इसकी आवश्यकता अनुभव की है और शब्दावली को अधिक स्पष्टरूप से इस पुस्तिका में सम्मिलित करने में अपना योगदान दिया है।

मुझे विश्वास है कि पाठक अपने ज्ञानवर्धन और शब्दावली को समझने के लिए इस पुस्तिका को काफी लाभदायक पाएंगे।

नई दिल्ली
24 अप्रैल 2015

सीए. मनोज फडनीस
प्रेजीडेंट, आई सी ए आई

आमुखम्

लोग अपने जीवनकाल में जो भी निर्णय लेते हैं उनमें वित्तीय निर्णयों का अहम स्थान है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम लोगों को ऐसे बेहतर साधन प्रदान करें जिससे उन्हें अपने वित्तीय निर्णय लेना सहज हो। आज समाज में तरह-तरह के जटिल वित्तीय उत्पाद विकसित हो रहे हैं और इन वित्तीय उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग पूरी तरह से वित्तीय जानकारी रखें।

'सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा में सामान्यतया प्रयुक्त शब्दावली' पर प्रस्तुत पुस्तिका वित्तीय शब्दावली से परिचित होने में सहायक है। यह पुस्तिका एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अपरिचित और जानकारी से परे की वित्तीय कारोबार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह पुस्तिका वित्तीय सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रबंधकों और स्टाफ, वित्तीय मामलों के परामर्शदाताओं, सरकार न्यामकों और सेवा-कम्पनियों को उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली को समझने में उपयोगी है।

यह आशा की जाती है कि सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा के विषय के सुधी पाठक विषयगत शब्दावली को समझने के लिए इस पुस्तिका को उपयोगी पाएंगे।

इस पुस्तिका को तैयार करने में जिन व्यक्तियों ने प्रयास किया है में उनका आभारी हूँ।

नई दिल्ली
16 अप्रैल 2015

सीए विजय गर्ग
अध्यक्ष, सीपीएफ एण्ड जीए

आभार

किसी भी देश का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सरकारी वित्तीय रिकार्ड एक विवेकपूर्ण लेखा प्रणाली और मजबूत व प्रभावी व्यवहारों और आन्तरिक जांच व नियंत्रण पर आधारित होना चाहिए ताकि सार्वजनिक निधियां पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। सरकारों की सार्वजनिक वित्त का कार्य-निष्पादन इस बात से देखा जाता है कि वे बढ़ती वैश्विक संकल्पना में आर्थिक विकास की चुनौतियों से कैसे मुकाबला करती हैं और किस तरह अपनी न्यामक व सुदृढ़िकरण की भूमिका को निभाती हैं।

इस पृष्ठभूमि में सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा समिति ने 'सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा में सामान्यतया प्रयुक्त शब्दावली' पर अपनी पुस्तिका को प्रकाशित किया है ताकि सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा के क्षेत्र में प्रयुक्त शबदावली को बेहतर रूप से समझने में सहातया मिल सके।

सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा समिति, आईसीएआई उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करती है जिन्होंने पुस्तिका के प्रकाशित संस्करण को तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उनके अमूल्य सुझावों व रचनात्मक विचारों के प्रति भी आभारी हूँ जिनसे यह पुस्तिका इस बेहतर रूप में हमारे समक्ष है।

इस प्रयास में समिति के सचिव डा. निखिल साकेत और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों ने प्रशंसनीय योगदान दिया है, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ।

नई दिल्ली
अप्रैल 2015

सीए विजय गर्ग
अध्यक्ष
सीपीएफ एण्ड जीए

सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखा में सामान्यतया प्रयुक्त शब्दावली

A

कमी (Abatement)

कर-योग्य मूल्य में कटौती या कमी जो कर-निर्धारण और उगाही (लेवी) के बाद करों में कटौती की जाती है।

लेखा प्रणाली (Accounting System)

लेखा विधियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का मैनुअल और कम्प्यूटरीकृत संगठित सैट जिसे वित्तीय आंकड़ों को एकत्र करने, रिकार्ड करने, वर्गीकृत करने, विश्लेषण करने, संक्षिप्त करने, व्याख्या करने और समय पर व सही-सही प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया जाता है ताकि प्रबंधकीय निर्णय लिये जा सकें।

आस्तियाँ (Assets)

एक ऐसा संसाधन जिसका एक आर्थिक मूल्य होता है और उसे एक व्यक्ति, निगम या देश इसलिए ग्रहण या नियंत्रित करता है कि उसे भविष्य में किन्हीं लाभों की आशा रहती है।

पूर्ण लाभ (Absolute Advantage)

यह आर्थिक कार्य-निष्पादन का सरलतम माप है। जब एक व्यक्ति फर्म या देश उसी श्रम व उन्हीं संसाधनों से अधिक उत्पादन करता है तो वह अन्य उत्पादक की तुलना में पूर्ण लाभ प्राप्त करता है।

यह एक व्यक्ति, फर्म या देश की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अन्य उत्पादक की तुलना में कम लागत व श्रम से उसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है।

यथामूल्य कर (Ad-Valorem Tax)

ये वे शुल्क हैं जो उत्पाद की कीमत के लिए निश्चित प्रतिशत पर निर्धारित किये जाते हैं।

परिशोधन (Amortization)

एक आस्ति के उपयोगी जीवन काल के दौरान इसकी लागत के यथानुपात में मूल्य में काटौती।

लेखा नीतियां (Accounting Policies)

एक उद्यम द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट लेखा सिद्धान्त और उन सिद्धान्तों के प्रयोग की विधियां।

लेखा का प्रोद्भवन आधार (Accural Basis of Accounting)

लेनदेनों के रिकार्ड करने की वह विधि जिसके द्वारा राजस्व लागतें, आस्तियां और दायित्व उस अवधि के लेखों में प्रदर्शित किये जाते हैं जिसमें कि वे प्रोद्भूत होते हैं। 'लेखा के प्रोद्भवन आधार' में स्थगन, आबंटन, मूल्यह्रास और परिशोधन से सम्बंधित प्रतिफल सम्मिलित रहते हैं। इस आधार को लेखा का वाणिज्यिक आधार भी कहा जाता है।

सकल मांग का सिद्धान्त (Aggregate Demand Theory)

सकल मांग का सिद्धान्त आर्थिक उत्पादन, मांग व उपभोग के मध्य सम्बन्ध को स्पष्ट करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, यदि कुल मांग और उपभोग के मूल्य में कमी आती है तो आर्थिक उत्पादन भी घट जाता है।

सकल व्यय (Aggregate Expenditure)

सकल व्यय एक अर्थव्यवस्था की समस्त तैयार वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विधि है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक गतिविधियों की कुल राशि की गणना की जाती है। इसे अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद् (जी डी पी) भी कहा जाता है।

सकल उत्पादन (Aggregate Output)

एक दी गयी अवधि में, जो सामान्यतया एक वर्ष की होती है, अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग। अर्थव्यवस्था के सकल उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद् (जी डी पी) भी कहा जाता है।

सकल आपूर्ति (Aggregate Supply)

एक दी गयी अवधि में एक दिये गये मूल्य (कीमत) स्तर पर एक बाज़ार में आपूर्ति की गयी वास्तविक वस्तुओं व सेवाओं की कुल राशि।

सकल आपूर्ति मूल्य वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या सकल 'जीडीपी' के समान होता है।

मूल्यांकन (Appraise)

मूल्य का आंकलन विशेष कर सम्पत्ति के मूल्य का।

मूल्य-वृद्धि (Appreciation)

आस्ति के मूल्य में वृद्धि जो कि मूल्यह्रास (depreciation) का विपरीतार्थी है। जब एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा की कीमत की तुलना में बढ़ जाती है तो इसे मूल्य में बढ़ी हुई कहा जाता है और यह अपेक्षया अधिक मजबूत मानी जाती है।

आबंटन कार्य (Allocation Function)

सरकार के वे कार्य जिनसे संसाधनों का उपयोग उस बाजार आबंटन से बदल जाता है जिससे कि अन्यथा उत्पादन अपेक्षित था।

मूल्यांकन अनुपात (Appraisal Ratio)

बाज़ार मूल्य के सूचक के मूल्यांकित मूल्य का अनुपात। म्यूचल फंडों के संदर्भ में यह एक ऐसे जोखिम के प्रति यूनिट असामान्य प्रतिफल (रिटर्न) का माप करता है जिसे मार्केट इन्डेक्स पोर्टफोलियो में रखकर विविधिकरण (Diversify) द्वारा कम से कम किया जा सकता है।

विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill)

वह विधेयक (बिल) जिससे संचित निधि से व्ययों का भुगतान करने के लिए धन निकाला जा सकता है। ये वे लिखतें (instruments) हैं जिन्हें संसद लोकसभा में अनुदानों (ग्रांटों) की मांग पर वोट करके पारित (clear) करती है।

अंतरपणन (Arbitrage)

अंतरपणन (Arbitrage) परिभाषा के रूप में एक ऐसा वित्तीय लेनदेन है जो बिना जोखिम तत्काल लाभ प्रदान करता है। तकनीकी रूप से एक पण्य (वस्तु) या प्रतिभूति

(security) को एक बाजार में खरीदकर तत्काल दूसरे बाज़ार में बेच दिया जाता है।

स्वायत्त निवेश (Autonomous investment)

स्वायत्त निवेश, निवेश का वह स्तर है जो राष्ट्रीय उत्पाद से निरपेक्ष है। इसमें सरकारी निवेश समाप्त पूंजी की पूर्ति के लिए निवेश या फिर ऐसा निवेश आता है जो किसी लक्ष्य के परिवर्तन पर निर्भर नहीं है।

औसत परिवर्तनशील लागत (Average variable cost)

कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादित ईकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत परिवर्तनशील लागत (AVC) प्राप्त होती है।

औसत लागत (Average cost)

कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देकर औसत लागत (AC) प्राप्त होती है।

बचत की सामान्य प्रवृत्ति (Average propensity to save)

यह एक आर्थिक शब्दावली है जिसका अर्थ है कि एक परिवार आय में से खर्च के बाद सामान्यतया कितना अंश बचाता है। बचत की सामान्य प्रवृति (APS) का विलोमार्थी है।

उपभोग की सामान्य प्रवृति (Average Propensity to Consume)

उपभोग की सामान्य प्रवृति आय में से व्यय का प्रतिशत है जिसे निकालने के लिए व्यय को आय द्वारा भाग देकर 100 से गुणा किया जाएगा। उपभोग की सामान्य प्रवृति (AVC) का विलोमार्थी बचत की सामान्य प्रवृति (AVP)।

आयात की सामान्य-प्रवृत्ति (Average propensity to import)

प्रत्येक व्यक्ति, परिवार या देश की कुल निपटान योग्य आय का वह भाग जिसे आयात पर खर्च करता है।

कर की औसत दर (Average Rate of Tax)

कर आधार (करयोग्य आय या व्यय) के लिए दिये गये कर का अनुपात कर की औसत दर (A R T) है।

औसत राजस्व (Average Revenue)

कुल राजस्व को कुल उत्पादन की मात्रा से भाग देकर उत्पादन की प्रत्येक ईकाई की राशि अथवा एक वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व।

सकल मांग (Aggregate Demand)

एक दी गयी अवधि के दौरान और एक दिये गये कीमत स्तर पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों (व्यक्तियों, कम्पनियों, सरकार व निर्यातकों) से वस्तुओं व सेवाओं की कुल (सकल) मांग। दूसरे शब्दों में, यह उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय व निवल निर्यात का जोड़ है।

प्रोद्भवन आधार (Accrual Basis)

लेखा का वह आधार जिसके अधीन राजस्व व व्यय उस अवधि के आधार पर रिकार्ड किये जाते हैं जब वे अर्जित किये जाते या जब उनके लाभ प्राप्त होते हैं भले ही उनके नकद लेनदेन कभी भी हों।

वैकल्पिक न्यूनतम कर (Alternative Minimum Tax)

जब कर दायित्व की गणना वैकल्पिक नियमों के सैट से की जाती है जिसमें उन व्यक्तियों को कुछ कर अदा करने के लिए विवश किया जाता है जिनकी अधिमान आय (Preference income) के उच्च स्तर हैं।

B

अशोध्य ऋण (Bad Debt)

अशोध्य ऋण वह ऋण है जो एक व्यक्ति या कारोबार के लिए दिया गया है लेकिन सभी तर्कसंगत प्रयासों के बावजूद चूंकि उसकी वसूली हो नहीं सकती है और चूंकि यह हानि है अतः इसे लेनदार बट्टे-खाते में डाल देता है (और इसे व्यय के रूप में वर्गीकृत करता है।) ऐसा आमतौर पर तब होता है जब देनदार स्वयं को दिवालिया घोषित कर देता है या ऋण की वसूली के लिए प्रयासों का व्यय ऋण की राशि से अधिक होने की संभावना हो।

सन्तुलित बजट (Balanced Budget)

बजट की ऐसी स्थिति जहां राजस्व और व्यय दोनों समान हों। यह बजट की आदर्श स्थिति है। अर्थशास्त्री जे॰ एम॰ कीन्स का मत था कि सरकारों को मंदी के दौरान घाटे (डेफिसिट) का बजट बनाना चाहिए ताकि आर्थिक क्रियाएं उठ सकें और तेजी (बूम) के दौरान बेशी (सरप्लस) का बजट बनाना चाहिए ताकि आर्थिक क्रियाएं मंद पड़ें।

तुलन-पत्र (Balance Sheet)

एक उद्यम की एक तिथि पर वित्तीय स्थिति का विवरण जिसमें उसकी आस्तियों, दायित्वों, पूंजी प्रारक्षित निधि और लेखे के अन्य शेष पुस्तक मूल्य (बुक वैल्यु) पर दिये जाते हैं।

बैंक दर (Bank Rate)

यह वह दर है जिस पर एक देश का केन्द्रीय बैंक (भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक) वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यह वह वित्तीय उपकरण (टूल) है जिसे केन्द्रीय बैंक अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं के लिए प्रयोग में लाता है।

सन्तुलित बजट गुणक (Balanced Budget Multiplier)

गुणक यह उल्लेख करता है कि सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में भी उतनी ही वृद्धि इन दोनों से उत्पादन में वृद्धि होती है।

भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments)

एक स्वयंभू राष्ट्र के निवासियों (Residents) और अन्य राष्ट्रों के निवासियों (Residents) के सभी आर्थिक लेनदेनों का सांख्यिक विवरण, जो एक अवधि सामान्यतया एक वर्ष का होता है।

आधारभूत मुद्रा (Base Currency)

वह मुद्रा जिसमें अन्य देशों की मुद्रा का उल्लेख किया जाता है।

अंकित मूल्य (Book Value)

वह राशि जिसमें एक मद को लेखा पुस्तकों या वित्तीय विवरणों में दिखाया जाता है। इसे किसी विशेष आधार, जैसे कि लागत, पुनर्स्थापन मूल्य, आदि, के संदर्भ में नहीं दिया जाता।

आधार वर्ष (Base Year)

व्यय समीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष से एकदम पिछला वर्ष।

आधार अवधि (Base Period)

आर्थिक आंकड़ों (डाटा) के माप की तुलना के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त एक विशेष अवधि।

आधार बिन्दु (Basis Point)

प्रतिशत बिन्दु का 1/100 अंश। ब्याज-दर, विनिमय-दर और बाँड में छोटे से भी परिवर्तन प्रायः आधार बिन्दुओं द्वारा वर्णित किये जाते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि बाँड की प्राप्ति (ईल्ड) 5.25% से बदलकर 5.45% हो जाती है तो इसे 20 आधार बिन्दु (बेसिंस प्वाइंट) बढ़ा हुआ माना जाएगा।

आधारभूत बजट (Base Budget)

चालू बजट वर्ष में सेवा के वर्तमान स्तरों के चालू रहने की लागत।

वस्तु-विनिमय (Barter)

वस्तुओं या सेवाओं का भुगतान धन में न करके अन्य वस्तुओं या सेवाओं द्वारा करना। यह प्रणाली तभी प्रचलित होती है जब धन की गुणवत्ता मुद्रास्फीति के कारण न्यून या अनिश्चित हो या तब जब लोग आस्ति-समृद्ध हों लेकिन नकदी रूप से कमजोर हों या फिर जब कराधान या अपराधियों का दबाव (extortion) अधिक हो।

विधेयक (Bill)

विधेयक कानूनी प्रस्ताव का वह प्रारूप जो संसद के दोनों सदनों में पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियम (Act) का रूप लेता है।

बजट (Budget)

एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान विशेष सेवाओं, प्रयोजनों और कार्यों के समर्थन में संसाधनों के आबंटन का एक प्लान।

उधार (Borrowings)

विकास परियोजनाओं और/अथवा बजट सहायता के वित्त पोषण के लिए वापसी योग्य

संसाधनों से प्राप्त निधियां जिनमें वित्तीय संसाधनों और आन्तरिक व बाह्य दोनों अन्य स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त ऋण भी सम्मिलित हैं।

वृहद धन (Broad Money)

धन आपूर्त्ति की गणना, जिसमें तरल नकदी और ऐसा धन जो खरीददारी में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे कि बैंकों में जमा धन, सम्मिलित है।

अपील बोर्ड (Board of Appeals)

एक सार्वजनिक निकाय (न्यायालय से भिन्न) जिन्हें करदाताओं की अपीलों को सुनने और निर्णय लेने का कार्य दिया गया है या न्यायालयों से भिन्न निकायों या लोक अधिकारियों द्वारा स्थापित कर निर्धारण जिले।

मंदड़िया (Bear)

मंदड़िया (Bear) तेजड़िया (Bull) का विलोमार्थी है। मंदड़िया निवेशक यह मानते हैं कि एक विशिष्ट प्रतिभूति या उद्योग का मूल्य भविष्य में घट सकता है।

कालाधन (Black Money)

काले धन में वे सभी आय सम्मिलित हैं जो हालांकि करयोग्य हैं लेकिन कर-प्राधिकारियों को रिपोर्ट नहीं की गयी हैं यानि उन पर कर (टैक्स) नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त कालाधन या बिना हिसाब की आय वह है जो राष्ट्रीय आय या उत्पाद को नीचे की ओर धकेलती है क्योंकि कर चोरी, अन्य आर्थिक नियंत्रणों और सम्बधित उद्देश्यों को ताक पर रखकर आदि कारणों से जानबूझ कर गलत रिपोर्टिंग की जाती है।

कालेधन की अर्थ-व्यवस्था (Black Economy)

देश की आर्थिक गतिविधि का वह खंड जो उन साधनों द्वारा चलाया जाता है जो देश के वाणिज्यिक नियमों व विनियमों से बाहर हैं।

सीमित तर्कसंगता (Bounded Rationality)

मानवीय निर्णय का वह सिद्धान्त जो यह मानता है कि विवेकपूर्ण रूप से व्यवहार करते हैं लेकिन केवल सूचना की उस सीमा तक जो उन्हें उपलब्ध है। चूंकि उनकी सूचना अपर्याप्त (सीमित) होती है अतः वे आर्थिक मानव के परम्परागत सिद्धान्तों के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं या कई बार उनके निर्णय विवेकरहित भी हो सकते हैं।

क्रेता का बाजार (Buyer's Market)

ऐसी बाज़ार व्यवस्था जहां क्रेताओं की संख्या विक्रेताओं की संख्या में अधिक होती है। अधिक आपूर्ति और कम मांग के कारण इस बाजार व्यवस्था में कीमतों का स्तर निम्न रहता है। इसे नरम बाजार भी कह सकते हैं। इसका विलोभार्थी विक्रेता बाजार (Seller's Market) है।

घाटे का बजट (Budget Deficit)

एक विशेष समयावधि के दौरान, सामान्यतया एक वर्ष जब सरकार के व्यय उसके आय संसाधनों से अधिक होते हैं। इस प्रकार का बजट घाटे का बजट कहलाता है।

बचत बजट (Budget Surplus)

एक विशेष समय अवधि के दौरान जब सरकार, निगम या व्यक्ति की आय की मात्रा व्यय की मात्रा से अधिक हो। इस प्रकार का बजट बचत का बजट (Budget Surplus) कहलाता है। जब एक सरकार का ऐसा बजट हो तो वह अधिक आय से या तो नये कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकती है या कर कम कर सकती है। एक निगम इस स्थिति में निवेश बढ़ाकर या अधिग्रहण करके कारोबार को बढ़ा सकता है या अपने स्टाक की पुनर्खरीद (Buy Back) कर सकता है। इस तरह, एक व्यक्ति इस प्रकार के बजट में ऋण का भुगतान, व्यय में वृद्धि या निवेश में से कोई भी विकल्प चुन सकता है। इसका विलोमार्थी घाटे का बजट (Budget Deficit) है।

बजट प्राक्कलन (Budget Estimate)

बजट प्राक्कलन में वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में व्यय का अनुमान और कर-राजस्व के रूप में आय का अनुमान होता है।

खंडीय अनुदान (Black Grants)

जब एक राष्ट्रीय सरकार क्षेत्रीय सरकार को धन की एक बड़ी मात्रा इस आशय से देती है कि उसे किस प्रकार से खर्च किया जाना है, इसे खंडीय अनुदान कहा जाता है।

तेजड़िया (Bull)

ऐसा निवेशक जो सोचता है कि एक विशेष प्रतिभूति या उद्योग ऊपर उठेगा और इस आशा में उस प्रतिभूति की खरीददारी करता है कि भविष्य में वह उसे अधिक कीमत

में बेचकर लाभ कमा लेगा, ऐसे निवेशक को तेजड़िया या सटोरिया (Bull) कहा जाता है और यह मंदडिया (Bear) का विलोमार्थी है।

बैंक गारंटी (Bank Guarantee)

जब कोई बैंक एक व्यक्ति या फर्म, की ओर से, सामान्यतया बैंक का ग्राहक, तीसरे पक्ष को इस आशय की गारंटी देता है कि उसके द्वारा किये गये अनुबंध में यदि कोई चूक होती है और उससे तीसरे पक्ष (Benefieiary) को वित्तीय हानि होती है तो उसकी भरपाई बैंक करेगा। इसके एवज में ग्राहक व्यक्ति या फर्म बैंक के साथ प्रतिपूर्ति व्यवस्था करती है। यह गारंटी एक सीमित अवधि व राशि तक सीमित होती है। इस गारंटी द्वारा ग्राहक (व्यक्ति या फर्म) अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वस्तुओं का अधिग्रहण, उपस्करों की खरीद या ऋण लेने आदि का कार्य कर सकता है।

C

पूंजी (Capital)

पूंजी एक व्यक्ति या समुदाय के धन (wealth) का वह भाग है जिसे संसाधनो ंकी वृद्धि जैसे कि मशीनें, के निमित्त प्रयोग में लाया जाता है।

पूंजी खाता (Capital Account)

एक देश का राष्ट्रीय खाता यह प्रदर्शित करता है कि उसने आधारभूत ढांचे (infrastructure) पर कितनी राशि व्यय की है। इसी तरह, एक फर्म का खाता संयंत्र और अन्य आस्तियों में किये गये निवेश को प्रदर्शित करता है।

उद्योग संगठन (Cartel)

प्रतिस्पर्धा में फर्मों के बीच यह एक औपचारिक संगठनात्मक ढांचा है जो एक औपचारिक करार में वद्ध है। इसमें विक्रेता फर्मों की सीमित संख्या होती है और वे एक जैसे उत्पाद् का निर्माण करती हैं। संगठन के सदस्य कीमत निर्धारण, उद्योग का कुल उत्पादन, मार्केट शेयर, ग्राहकों का आबंटन, क्षेत्रों का आबंटन, बोली व्यवस्था सामान्य सेल्स एजेंसियों की स्थापना, लाभ वितरण जैसे किसी एक या अनेक मामलों पर परस्पर सहमति कर सकते हैं। इस प्रकार के संगठन (जिसे उद्योग-संगठन करार भी

कहा जाता है) का उद्देश्य है कि प्रतिस्पर्धा को कम किया जाए और व्यक्तिगत सदस्यों के लाभ में वृद्धि हो।

दुरभिसंधि (Collusion)

दो व्यक्ति (या कारोबारी प्रतिष्ठान अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) जब एक ऐसी सहमति कर लेते हैं कि तीसरी पाटी (प्रतिस्पर्धा में अन्य व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों या उपभोक्ताओं या फिर उनसे जिनसे कोई लेन देन तय किया जाना है। धोखा देकर लाभ या नाजायाज फायदा उठाया जाए। उनकी आपसी सहमति या करार गोपनीय रहता है। इस प्रकार के गठजोड़ या दुरिभसंधि में गुप्त कीमत या मजदूरी का निर्धारण, गुप्त छूट या देखने में अलग लगना जबकि अपने स्वार्थ के लिए एक-साथ होना, जैसे मामले आ सकते हैं।

पूंजीगत बजट बनाना (Capital Budgeting)

अनेक उपलब्ध विकल्पों के बीच फर्म की दीर्धवधि पूंजीगत आस्तियों की चयन-प्रक्रिया। यह तकनीक केवल नकदी प्रवाहों पर आधारित है।

पूंजीगत वचनबद्धता (Capital commitment)

पूंजीगत व्यय के लिए भावी दायित्व जिसके लिए अनुबंध किये गये हैं।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditures/Outlays)

भौतिक आस्तियों, जैसे कि सम्पत्ति, औद्योगिक भवन, या उपस्कर के अधिग्रहण या उन्नयन (upgradation) के लिए एक कम्पनी द्वारा प्रयुक्त निधियां। इस प्रकार के व्यय कम्पनियां अपने परिचालनों का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए करती हैं। इस प्रकार के व्यय में छत की मरम्मत से लेकर एक शानदार नई फैक्टरी लगाने तक सभी कुछ सम्मिलित हैं।

पूँजीगत आरक्षित निधि (Capital Reserve)

एक कार्पोरेट प्रतिष्ठान की आरक्षित निधि जो लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

पूंजी का बर्हिगमन (Capital Flight)

किसी देश की राजनैतिक अस्थिरता, युद्ध या अन्य परिस्थितियों के कारण जब देश की आर्थिक स्थिति भरोसे लायक नहीं रहती है और पूंजी का तेजी से देश से बहिर्गमन होता है तब उसे पूंजी का बर्हिगमन कहते हैं।

पूंजीकरण (Capitalization)

ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा करों का एक अंश आस्ति की कीमत में सम्मिलित हो जाता है।

पूंजीगत राजस्व (Capital Revenue)

स्थिर या पूंजीगत आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियां, जैसे कि, भूमि, भवन, मशीनरी, स्टॉक व अमूर्त्त आस्तियां जिनमें गैर-सरकारी स्रोतों से पूंजी प्रयोजनों के लिए चुकायी न गयी अन्तरण प्राप्तियां भी सम्मिलित हैं।

पूंजीगत अन्तर्प्रवाह (Capital inflow)

एक देश में कम्पनियों में शेयर खरीदकर, पूरी कम्पनियां खरीदकर या निवेश के अन्य स्वरूपों द्वारा पूंजी का प्रवेश।

नकदी आरक्षित अनुपात (CRR)

भारत में, बैंकों को प्राप्त जमाराशियों (deposits) का एक निश्चित भाग अपने पास नकद रूप रखना आवश्यक है। लेकिन, बैंक उसे अपने पास नकद न रखकर या तो भारतीय रिजर्व बैंक में या करंसी चेस्टों में जमा कर देते हैं। करंसी चैस्टों में जमा की गयी नकदी भी भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की तरह ही होती है।

पूंजी निर्माण (Capital Formation)

बचत द्वारा पूंजी या पूंजीगत वस्तुओं के प्रसार से एक देश की आर्थिक प्रगति होती है या वास्तविक पूंजी के स्टॉक में निरन्तर वृद्धि होती है। इनमें मशीनें, उपकरण आदि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी शामिल है जो आगे और वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त की जाती हैं।

पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)

पूंजीगत आस्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसे पूंजीगत लाभकर कहा जाता है।

पूंजीगहन (Capital intensive)

एक व्यवसायिक प्रक्रिया या उद्योग जिसमें वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए धन की बड़ी राशि और अन्य वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहती है। एक व्यवसाय के संचालन में जब श्रम की तुलना पूँजी का अनुपात अधिक हो तो उसे पूंजी गहन व्यवसाय कहा जाता है। इसी तरह, जहां पूंजी की वजाय श्रमिकों की अधिक आवश्यकता हो तो उस व्यवसाय को श्रमिक गहन व्यवसाय कहा जाता है। सामान्यतया, तेल उत्पादन, रिफाइनिंग, दूरसंचार और परिवहन (रेलवे, एअरलाइनें आदि) जैसे उद्योग पूंजी गहन व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं जबकि कृषि श्रमिक गहन में।

करों का पूंजीकरण (Capitalization of Taxes)

सम्पत्ति के प्रत्याशित करों का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने और सम्पत्ति का मूल्य तदनुसार समायोजित करने के कार्य को करों का पूंजीकरण कहा जाता है।

नकदी बजट (Cash Budget)

यह एक नकदी प्रवाह का विस्तृत प्लान होता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान नकदी संसाधनों की प्राप्ति (अन्तर्प्रवाह) और उपयोग (वहिर्प्रवाह) को दर्शाता है।

जब अन्य बातें समान हों (Ceteris Paribus)

एक लैटिन कहावत जिसका अर्थ है 'जब अन्य बातें समान हों'। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था पर एक कारक का क्या प्रभाव देखा जाता है। इस स्थिति में यह मान लिया जाता है कि अन्य कारक स्थिर हैं यानि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

बन्द अर्थव्यवस्था (Closed Economy)

एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेती है उसे बन्द अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income)

उत्पादकों और उन परिवारों के बीच आय का प्रवाह जो उत्पादकों की वस्तुओं या सेवाओं को क्रय करते हैं। जब परिवार चीजें या सेवाएं खरीदते हैं तो आय परिवारों से उत्पादकों की ओर प्रवाहित होती है और वेतन या लाभों के रूप में यही आय उत्पादकों से परिवारों की ओर प्रवाहित होती है।

अन्तर्सम्बन्ध (Cointegration)

सांख्यिकी में, दीर्घवधि में मापे गये आर्थिक आंकड़ों (डाटा) के बीच सम्बंध की गणना।

संकुचित राजकोषीय नीति (Contractionary Fiscal Policy)

सरकार की वह नीति जिसका उद्देश्य सरकार के व्यय को घटाना या करों में वृद्धि करना है। इन दोनों से ही अर्थव्यवस्था की मांग में कमी आ जाती है। इसे मुद्रास्फीति शील राजकोषीय नीति भी कहा जाता है।

संचित निधि (Consolidated fund)

संचित निधि में सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, इसके द्वारा लिये गये ऋण, इसके द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली, आदि सम्मिलित हैं।

आकस्मिक निधि (Contigency Fund)

आकस्मिक निधि एक प्रकार की आरक्षित निधि है जो इस प्रयोजन से अलग रखी जाती है कि सामान्य परिचालन बजट से बाहर कोई अप्रत्याशित देनदारी उत्पन्न हो तो उसे इस निधि में से पूरा किया जाए। यह आकस्मिक मॉडल संकटकालीन स्थिति में संभावित हानि से बचने के लिए तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग कई परिस्थितियों में किया जा सकता है। सरकारें, निजी व्यवसाय और यहां तक कि व्यक्तिगत परिवार भी इस प्रकार की निधि बनाकर इसे समग्र वित्तीय प्लान का अंग बना सकते हैं।

आकस्मिक दायित्व (Contigent Liability)

ऐसी वाध्यता जो वर्तमान या भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति में होने या न होने वाली एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं से उत्पन्न हो सकती है।

एकीकरण (Convergence)

संसाधनों का एकीकरण एक विशेष गतिविधि के लिए विभिन्न एजेंसियों के संसाधनो व ताकतों को इकट्ठा करना है। इसके लिए आयोजकों को प्रत्येक एजेंसी की योजनाओं और उपलब्ध भौतिक व वित्तीय संसाधनों पर नजर डालना आवश्यक है ताकि वे प्रत्येक को इस तरह से सम्बद्ध कर सकें ताकि सभी एक के अंग बन जाएं।

चालू आस्तियां (Current Assets)

नकदी और अन्य आस्तियां जो नकदी में परिवर्तित हो सकती हैं या कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में वस्तुओं के उत्पादन या सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हैं।

परिवर्तनीयता (Convertability)

जब एक बांड, डिबेंचर या अधिमान शेयर का विनिमय स्वामी द्वारा सामान्य स्टॉक या अन्य प्रतिभूति, जो सामान्यतया उसी कम्पनी की हो, निर्गम की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

चालू परिचालनगत व्यय (Current Operating Expenses)

बजट वर्ष के दौरान, सामान्य सरकारी परिचालनों के संचालन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु अनुमानित राशि। इसमें वे वस्तुएं और सेवाएं भी सम्मिलित हैं जो बजट वर्ष के दौरान उपयोग में लायी जाएगी।

लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit Analysis)

एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम प्रत्याशित लागत के मुकाबले प्रत्याशित लाभों का निर्धारण करते हुए उसे सर्वोत्तम (या सर्वाधिक लाभकारी) मानते हैं।

सीमा-शुल्क (Custom)

जब कोई वस्तु निवेश से एक कीमत पर खरीदकर देश के अन्दर लायी जाती तो उसे आयात कहते हैं। सरकार इस आयात पर एक कर (शुल्क) लगाती है जिसे सीमा शुल्क कहा जाता है। इससे सरकार का दोहरा फायदा है, एक सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है तो दूसरे आयात को निरुत्साहित कर स्थानीय उद्योगों का बचाव या संवर्द्धन होता है।

सुस्त मुद्रा स्फीति (Creeping inflation)

मुद्रास्फीति की सामान्य प्रक्रिया जो अनेक देशों में है और वह प्रतिवर्ष धीरे-धीरे बढ़ती है।

सूक्ष्म पथ विश्लेषण (Critical Path Analysis)

एक परियोजना को न्यूनतम समय में पूरा करने, उसके कार्यों को परिभाषित करना और यह पता करना कि प्रत्येक कार्य में कितना समय लगेगा, उन्हें इस तरह से रखना कि

प्रत्येक कार्य और समग्र परियोजना समय पर पूरी हो जाए। इन कार्यों में कौन से कार्य प्राथमिक हैं और कौन से ऐसे हैं जिन्हें बाद में किया जा सकता है ताकि परियोजना का बाकी कार्य सुचारू रूप से चलता जाए। इस प्रकार का विश्लेषण सूक्ष्म पथ विश्लेषण कहलाता है।

अधिक उधारी का प्रभाव (Crowding out effect)

एक आर्थिक सिद्धान्त जो यह प्रकट करता है कि जब सरकार की उधारी मनी मार्किट में बढ़ जाती है तो ब्याज-दरें बढ़ने लगती हैं।

सांपार्श्विक (Collateral)

ऋणी द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के पास एक आस्ति बंधक रखना पड़ती है ताकि जब ऋणी ऋणदाता के ऋण (मूल व ब्याज) को समय पर चुकाने में असमर्थ हो तो ऋणदाता उस आस्ति को जब्त कर सकता है। यह बंधक आस्ति सांपर्श्विक प्रतिभूति होती है।

नियंत्रित अर्थव्यवस्था (Command Economy)

जब सरकार आर्थिक क्रिया के सभी पक्षो को नियंत्रित करती है तब अर्थव्यवस्था का स्वरूप नियंत्रित अर्थव्यवस्था का हो जाता है।

प्रतियोगी लाभ (Competitive Advantage)

एक फर्म जब अपने प्रतियोगियों के बीच एक लाभ प्राप्त करती है जिसके अन्तर्गत उसे अन्य की अपेक्षा अधिक बिक्री या मार्जन मिलता है और/अथवा वह अधिक ग्राहक रख सकती है। ऐसे लाभ अनेक प्रकार के हो सकते हैं जिनमें लागत संरचना, उत्पाद की प्रस्तुति, वितरण नेटवर्क और ग्राहक समर्थन आदि सम्मिलित हैं।

मुद्रा की मूल्य वृद्धि (Currency Appreciation)

जब एक मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा के मूल्य की तुलना में बढ जाता है तो उसे मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहा जाता है। इसे परिवर्तनशील (अस्थिर) दर-विनिमय प्रणाली में मुद्रा के बाह्य मूल्य में वृद्धि भी कहा जा सकता है।

मूद्रा मूल्य में गिरावट (Currency Depreciation)

जब एक मुद्रा के मूल्य में दूसरी मुद्रा के मूल्य की तुलना में गिरावट होती है तो उसे मुद्रा

मूल्य में गिरावट या परिवर्तनशील (अस्थिर) दर-विनिमय प्रणाल में बाह्य मूल्य में गिरावट भी कहा जाता है।

मुद्रा विनिमय (Currency Swap)

जब एक मुद्रा के बदले में दूसरी मुद्रा द्वारा भुगतान करने का अनुबंधात्मक करार किया जाता है। इस अनुबंध में शामिल दो कम्पनियों में से कोई भी एक कम्पनी दूसरी की तुलना में दोनों में से किसी भी एक मुद्रा को अधिक अनुकूल दर पर खरीद सकती है।

चालू व्यय (Current Expenditure)

इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वेतन और सेवाएं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, प्रदान करने सम्बंधी प्रत्यक्ष व्यय आते हैं। ये व्यय प्रत्येक वर्ष वित्तपोषित शाश्वत कार्यक्रमों को प्रदर्शित करते हैं।

उपभोग कर (Consumption Tax)

एक निश्चित समयावधिक के दौरान, उपभोग की गयी वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य पर कर।

उपभोक्ता बेशी (Consumer surplus)

एक वस्तु या सेवा के उपभोग के लिए जब एक उपभोक्ता अधिक राशि देने को तैयार होता है लेकिन वास्तव में, वह कम देता है इन दोनों के अन्तर को अर्थशास्त्र में उपभोक्ता बेशी कहा जाता है।

नकदी सीमाएं (Cash Limits)

जब सरकार एक वर्ष में किन्हीं सेवाओं या सेवा खंडों के लिए नकदी की सीमाएं प्रस्तावित या अधिकृत करती है।

पूँजीगत वस्तुएँ (Capital Goods)

वे मूर्त आस्तियां जो एक संगठन वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाता है। इनमें कार्यालय भवन, उपस्कर, मशीनरी आदि सम्मिलित हैं। उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन एक उत्पादन प्रक्रिया का उद्देश्य है।

केन्द्रीय वैट (Cenvat)

पूर्ववर्ती Modvat स्कीम के स्थान पर Cenvat एक केन्द्रीय वैट (टैक्स) है जो तैयार

माल पर अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को कम करता है। यह स्कीम अधिक व्यापक है और इसके अधीन ज्यादातर वस्तुएँ आती हैं।

पूंजीगत बजट (Capital Budget)

इसके अन्तर्गत पूंजीगत प्राप्तियां व भुगतान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कम्पनियों, निगमों व अन्य पक्षों को दिये गये ऋण व अग्रिम आते हैं। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व वैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों से ट्रेजरी विलों की बिक्री द्वारा उधार और निवेशी सरकारों से ऋण भी आते हैं।

ऋण दुर्लभता (Credit Crunch)

जब बैंक ऋण देना बन्द कर देते हैं या बांड मार्किट की तरलता शुष्क हो जाती है। ऐसी स्थिति तब होती है जब ऋणी जोखिम के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं।

विशेष अनुदान (Categorical Grant)

एक अन्तर-सरकारी भुगतान जिसका उपयोग पूर्णतया प्रतिवधात्मक होता है यानि प्राप्तकर्ता सरकार को वह राशि केवल निर्धारित उद्देश्य व विधि के अनुसार ही खर्च करनी होती है।

निगमित कर (Corporation Tax)

यह वह कर है जो कम्पनियों अर्जित लाभ पर चुकाती हैं।

पूंजीकरण (Capitalization)

लेखा में, जब आस्ति के अधिग्रहण की लागतों को आस्ति के कीमत में शामिल कर दिया जाता है।

करों का पूंजीकरण (Capitalization of Taxes)

जब करों की राशि को आस्तियों की कीमत में जोड़ दिया जाता है उसे करों का पूँजी करण कहते हैं।

लागत प्रेरक मुद्रास्फीति (Cost push inflation)

जब श्रम, कच्चा माल आदि निविष्टियों (inputs) की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है तब उसे लागत प्रेरक मुद्रास्फीति कहा जाता है। उत्पादन-कारकों की लागत वृद्धि से

इनकी आपूर्ति कम हो जाती है। चूंकि मांग स्थित होती है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से समग्र कीमत स्तर बढ़ जाता है।

संकुचित नीति (Contractionary policy)

यह देश के केन्द्रीय बैंक या वित्त मंत्रालय द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला वह समष्टि अर्थशास्त्रीय उपकरण (मैक्रो इकनामिक टूल) है जो अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करता है। इससे मुद्रा की आपूर्ति कम होती है और अन्ततः सरकार का खर्च भी घटता है।

भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)

संविधान की धारा 266(i) के अन्तर्गत सरकार द्वारा करों के रूप में यथा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क, सीमा-शुल्क समस्त राजस्व और सरकारी कारोबार करने की करों से भिन्न अन्य आय जो सरकार के खाते में जानी हैं, भारत की संचित निधि में जमा (क्रेडिट) की जाती हैं। इसी तरह, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचनाओं, ट्रेजरी बिलों द्वारा जो ऋण लिये जाते हैं (आन्तरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण (बाह्य ऋण) भी इसी निधि में जमा होते हैं। सरकार के सभी व्यय इसी निधि में से किये जाते हैं लेकिन कोई भी आहरण संसद की मंजूरी (प्राधिकार) के बिना नहीं किया जा सकता।

भारत की आकस्मिक निधि (Contigency Fund of India)

यह निधि भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 267 के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। आकस्मिकताओं से सम्बधित सभी लेनदेन, इस निधि में रिकार्ड किये जाते हैं। इस निधि का 'कार्पस' 50 करोड़ रुपये है। जब भी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है इस निधि में से अग्रिम के रूप में राशि आहरित की जाती है और संसद की अनुमति पर जब अतिरिक्त व्यय की मंजूरी प्राप्त हो जाती है तो इस निधि में उस राशि को जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार यह निधि सरकार के लिए एक अग्रदाय खाता (Imprest Account) का प्रयोजन पूरा करती है और इसका संचालन भारत के राष्ट्रपति की ओर से सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, करते हैं।

महानियंत्रक लेखा (Controller General Accounts)

महानियंत्रक लेखा भारत सरकार के प्रमुख लेखा सलाहकार हैं और वह लेखा प्रणाली के लिए एक तकनीकी रूप से कुशल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

वह हर माह व्यय, राजस्व, उधारी और घाटे का समीक्षात्मक विश्लेषण तैयार करके वित्त मंत्री को प्रस्तुत करते हैं। वह वार्षिक विनियोजन लेखा (सिविल) और संधीय वित्त लेखा संसद में प्रस्तुति के लिए भी तैयार करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (Controller & Auditor General of India)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (कैग) भारत के संविधान की धारा 148 के अन्तर्गत वह प्रधिकारी है जो भारत सरकार, राज्य सरकारों व उन निकायों एवं प्राधिकरणों की, जिन्हें अधिकांश रूप से भारत सरकार द्वारा वितपोषित किया गया है, सभी प्राप्तियों व व्यय की लेखा-परीक्षा करता है। 'कैग' सरकार के स्वामित्व में निगमों का भी वाह्य लेखा परीक्षक है और सरकारी कम्पनियों यानि उन गैर-बैंकिंग व गैर-बीमा कम्पनियों जिनमें केन्द्र व राज्य सरकारों का ईक्विटी शेयर कम-से-कम 51 प्रतिशत है या वर्तमान सरकारी कम्पनियों की अनुषंगी कम्पनियों की पूरक लेखा परीक्षा करता है।

लेखे का नकदी आधार (Cash Basis of Accounts)

लेखा का वह आधार जिसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय को वास्तविक नकद प्राप्ति और वितरण पर रिकार्ड किया जाता है। सरकारी लेखा नकदी आधार पर रिकार्ड किया जाता है और उसमें अपवाद केवल उन्हीं पुस्तक समायोजनों में है जिन्हें नियमों या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेशों के अन्तर्गत प्राधिकृत किया जाता है।

D

चूक (Default)

ऋण करार की शर्तों को पूरा नहीं करना। उदाहरणार्थ, एक ऋणी चूक करता है जब वह ऋण के ब्याज का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं करता या करार के अनुसार निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान नहीं करता।

घाटा (Deficit)

जब सरकार का राजस्व व्यय से कम रहता है।

घाटे का वित्त (Deficit Financing)

जब सरकार राजस्व से ज्यादा खर्च करती है और घाटे को उधारी या अन्य नई निधियों से पूरा करती है। हालांकि, बजट घाटा कई कारणों से हो सकता है, लेकिन, यह शब्द आमतौर पर उस सजग प्रयास के रूप में प्रयुक्त होता है जब अर्थव्यवस्था को कर की दरें घटाकर या सरकारी व्यय बढ़ाकर चुस्त किया जाता है।

अपस्फीति (Deflate)

मुद्रास्फीति घटाकर आर्थिक गतिविधि का स्तर कम करना

ऋण सेवा (Debt Service)

विदेशी या घरेलू ऋणों में ऋण का भुगतान, ब्याज का भुगतान, वचनबद्धता फीस व अन्य प्रभारों का भुगतान।

ऋण बोझ (Debt Burden)

ऋण सेवा की लागत, यानि ऋण पर देय ब्याज का भुगतान।

ऋण राष्ट्र (Debtor Nation)

एक देश जिसके विदेशी ऋण अन्य देशों से प्राप्य राशि की तुलना में अधिक हैं।

ऋण पूंजीकरण दर (Debt Capitalization Rate)

समग्र प्रत्यक्ष पूंजीकरण दर में ऋण घटक। इसे वार्षिक ब्याज दर भुगतानों को ऋणों के बाजार मूल्य से भाग देकर निकाला जाता है।

ऋण विनिमय (Debt Swap)

ऐसे लेनदेन जिनमें एक फर्म एक देश का डालर बैंक ऋण बट्टे (डिस्काउन्ट) पर खरीदती है और उस ऋण का विनिमय केन्द्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्रा में करती है ताकि वह स्थानीय इक्विटी ग्रहण कर सके। इसे ऋण (डेट) इक्विटी विनिमय (स्वैप) भी कहा जाता है जिसमें कम्पनी मौजूदा बांडों (ऋणों या डेटों) को हाल में जारी स्टाक (इक्विटी) में विनिमयित करती है।

आस्थगित कर (Deferred Taxes)

एक गैर-नकदी व्यय जो निःशुल्क नकदी प्रवाह का स्त्रोत प्रदान करता है। अवधि के दौरान राशि का आबंटन उस कर दायित्व के लिए किया जाता है जिसका अभी भुगतान नहीं किया जाना है।

आस्थगित व्यय (Deferred Expenditure)

ऐसा व्यय जिसका भुगतान तो किया जा चुका है या दायित्व ग्रहण कर लिया है लेकिन उसे इस आशय से स्थगित रखा गया है कि बाद की अवधि या अवधियों में यह लाभकारी होगा। इसे आस्थगित राजस्व व्यय भी कहा जाता है।

आस्थगित राजस्व (Deferred Revenue)

आस्थगित राजस्व लेखा में वह धन है जो वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्राप्त हो चुका है लेकिन वे वस्तुएं या सेवाएं अभी प्रदान नहीं की गयी है। राजस्व मान्यता सिद्धान्त के अनुसार इसे तब तक एक दायित्व के रूप में रिकार्ड किया जाएगा जब तक वस्तुएं यह सेवाएं प्रदान नहीं की जातीं। लेकिन, एक समय के बाद, जैसे-ही वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान कर दिया जाएगा इसे आय विवरण में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी।

ऋण दर (Debt Rate)

उधार राशि की ब्याज-दर।

मूल्यह्रास (Depreciation)

सामान्यतया, एक आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान लागत को बट्टे खाते डालने के लिए अर्जन के प्रभार में से अवशिष्ट मूल्य घटा कर जो राशि बचती है वह मूल्यह्रास है। यह केवल एक पुस्तक प्रविष्टि मात्र है और यह न तो किसी नकद व्यय को प्रदर्शित करती है और न ही इस प्रयोज न के लिए कोई राशि चिन्हित की जाती हैं।

अवमूल्यन (Devaluation)

अवमूल्यन एक मुद्रा के मूल्य का दूसरी मुद्राओं के मूल्य की तुलना में कमी को इंगित करता है। एक स्थिर-दर स्थिति में केवल देश का केन्द्रीय बैंक ही अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है। अवमूल्यन विदेशी क्रेताओं को निर्यात कम खर्चीला और

घरेलू क्रेताओं को आयात अधिक खर्चीला बनाता है। इस तरह, अवमूल्यन से देश का व्यापार सन्तुलन या भुगतान सन्तुलन परिवर्तित होता है।

मूल्य में कमी (Depletion)

जब एक कम्पनी के तुलनपत्र से प्राकृतिक संसाधनों की लागत का परिवर्तन आय विवरणों में होता है तो उसे मूल्य में कमी कहते हैं। उद्देश्य यह है कि आय विवरण में बेचे गये प्राकृतिक संसाधनों की लागत को बेचे गये प्राकृतिक संसाधनों के राजस्व से मिलाना। बेचे गये प्राकृतिक संसाधनों की लागत को घटा हुआ व्यय कहा जाता है। अवधारणा के रूप में मूल्य में कमी (depletion) ठीक वैसा ही है जैसे कि सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर का मूल्यह्रास।

घटता क्रम शेष विधि (Diminishing Balance Method)

इसे घटता मूल्य विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार मूल्यह्रास एक नियत प्रतिशत पर लगाया जाता है और इस तरह आस्ति का पुस्तक मूल्य साल-दर-साल क्रमशः घटता जाता है और वह प्रतिवर्ष समान रूप से घटता है।

अवस्फीति (Disinflation)

जब मुद्रास्फीति की दर में कमी आती है। इसका अर्थ है कीमतों में वृद्धि तो होती है लेकिन कम दर पर होती है। इसका अर्थ कीमतों में गिरावट होना नहीं है। कीमतों में गिरावट की स्थिति को अपमुद्रास्फीति (Deflation) कहा जाता है।

निपटान योग्य आय (Disposable Income)

एक व्यक्ति की वह निजी आय जो करों और सरकारी शुल्कों (फीस) के बाद शेष रहती है और जिसे वह अपनी जरूरतों या अनावश्यक चीजों पर खर्च कर सकता है या फिर उसे बचा सकता है, इसे निपटान योग्य आय कहा जाता है।

दोहरी अर्थव्यवस्था (Dual Economy)

ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें तकनीकी रूप से उन्नत और तकनीकी रूप से पुरातन दोनों क्षेत्र साथ-साथ विद्यमान होते हैं। ऐसा प्रायः विकासशील देशों में होता है। जहां एक ओर तो खनिजों को निकालने के लिए या विनिर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी कर प्रयोग किया जाता है, वहीं देश के अधिकांश भाग के लोग गुजर-बसर स्तर का जीवन बिताते हैं।

छद्म परिवर्तनशील कारक (Dummy Variable)

ऐसा परिवर्तनशील कारक जिसका मूल्य या तो '1' है या फिर 'O' है, यानि उसमें कोई विशेषता हो भी सकती और नहीं भी हो सकती है।

अनुदानों की मांग (Demand for Grants)

संचित निधि से व्यय प्राक्कलन का विवरण जिस पर लोकसभा का अनुमोदन अपेक्षित है।

लाभांश (Dividend)

कम्पनी के लाभ का वह भाग जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। यह लाभ का विनियोजन है, न कि लाभ पर कोई प्रभार। अतः लाभ पर कर की गणना के लिए इसे लाभ में से घटाया नहीं जाता है।

असमानता को दूर करने के लिए कटौती सहायता (Disparity Reduction)

स्थानीय कर दरों को समान बनाने के संयोजन के लिए एक सहायता कार्यक्रम को डिजाइन करना।

वितरण कार्य (Distribution Function)

यह लोगों के बीच आय व धन के वितरण पर सरकार के प्रभाव से सम्बंधित है।

प्रभावी फर्म (Dominant Firm)

एक फर्म जो बाज़ार में कीमत निर्धारित करने की योग्यता रखती है।

विविधीकरण (Diversification)

वह प्रक्रिया जिसमें निवेशों को फैलाया जाता है यानि अलग-अलग विकल्पों में वितरित किया जाता है इससे एक जगह ही निवेश की मात्रा सीमित हो जाती है और जोखिम भी कम हो जाता है। लोग इसके लिए एक ही कम्पनी के शेयर न लेकर कई कम्पनियों के शेयर लेते हैं। इसी तरह, वे शेयरों के साथ-साथ डिबेंचर, म्यूचल फंड, सावधि जमा (एफडी) और अन्य निवेश विकल्पों में निवेश करते हैं। कम्पनियां भी अपने व्यवसाय को एक ही चीज पर केन्द्रित न करके नये और परस्पर असम्बद्ध क्षेत्रों में जाकर विस्तृत करती हैं।

'डम्पिंग' (Dumping)

जब वस्तुओं की बिक्री एक विदेशी बाजार में स्थानान्तरण की सभी लागतों, जिनमें परिवहन प्रभार और शुल्क भी सम्मिलित हैं, को लगाकर उस कीमत पर बेचा जाता है जो गृह-देश से भी कम है तो उस स्थिति को 'डम्पिंग' कहा जाता है। इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, बेशी स्टाक को निकालना या विदेशी प्रतियोगिता को समाप्त करना आदि कुछ भी हो सकता है।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

जो कर व्यक्ति या संगठन द्वारा निर्धारक प्रतिष्ठान या प्राधिकारी को सीधें ही अदा किया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। एक करदाता प्रत्यक्षकर सरकार को भिन्न-भिन्न प्रयोजनों से अदा करता है, जैसे कि 'रियल' सम्पत्ति कर, व्यक्तिगत सम्पत्ति कर, आयकर या आस्तियों पर कर।

व्युत्पन्न (Derivatives)

एक ऐसी प्रतिभूति जिसकी कीमत या तो किसी अन्य प्रतिभूति पर निर्भर है या फिर एक या अनेक अन्तर्हित आस्तियों से ली गयी है। व्युत्पन्न अपने आप में दो या दो से अधिक पक्षों के बीच केवल एक अनुबंध (Contract) है। इसका मूल्य अन्तर्हित आस्ति में उतार-चढ़ाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। सबसे ज्यादा आम अन्तर्हित आस्तियों में, स्टाक (शेयर), बाँड, पण्य, मुद्राएं, ब्याज-दरें और बाजार सूचकांक सम्मिलित हैं।

विकास व्यय (Developmental Expenditure)

विकास व्यय में वे व्यय आते हैं जो आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्सहित करते हैं। मूलभूत ढांचे के विकास पर किया जाने वाला व्यय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान या कृषि का विकास अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है और सरकार को राजस्व प्रदान करता है।

E

अर्जन (Earnings)

एक सामान्य शब्द, जिसमें राजस्व, लाभ या निवल आय सम्मिलित हैं।

व्यय (Expenses)

लेखा वर्ष के दौरान परिचालनगत लागत या अवधि के दौरान अर्जित राजस्व की लागत या जिसके लाभ उस अवधि से आगे नहीं जाएंगे।

इकनोमेट्रिक मॉडल (Econometric Model)

अर्थव्यवस्था के एक पक्ष का मॉडल जिसमें सांख्यिकी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मॉडलों का प्रयोग मेक्रो-इकनामिक प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है।

अर्जन-कीमत अनुपात (ई/पी) (Earnings – Price Ratio)(E/P)

एक लेखा अवधि में एक विशिष्ट कम्पनी के आम शेयर-धारक को उपलब्ध प्रति शेयर के अर्जन का उस कम्पनी के सामान्य स्टाक के प्रति शेयर की बाज़ार कीमत का अनुपात। E/P अनुपात का विलोभार्थी कीमत-अर्जन अनुपात (P/E) है। (E/P) अनुपात ईक्विटी की एक प्रत्यक्ष पूंजीकरण दर है, न कि प्राप्ति दर।

प्रतिशेयर अर्जन (Earning Per Share)

मौद्रिक अर्थ में अर्जन वह राशि है जो प्रत्येक इक्विटी शेयर पर विचाराधीन अवधि के निबल (शुद्ध) लाभ के आधार पर लेकिन पूर्व अवधि की मदों, असामान्य मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप समायोजनों और कर की कटौती व अधिमान लाभांशों के बाद जो शेष राशि बचती है उसको उस अवधि के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर और लाभांशों की रैंकिंग करके निकाला जाता है। इसे कम्पनी के कार्य-निष्पादन का एक महत्वपूर्ण माप माना जाता है।

आर्थिक विकास (Economic Development)

एक अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता में हुए परिवर्तन को आर्थिक विकास माना जाता है। आमतौर पर, इसे नई प्रौद्योगिकियों के ग्रहण करने, कृषि से उद्योग की ओर परिवर्तन और जन-जीवन के स्तर में सामान्यतया क्या सुधार हुआ है, इस संदर्भ में देखा जाता है।

आर्थिक कार्य कुशलता (Economic Efficiency)

एक ईकाई उत्पादन में प्रयुक्त निविष्टियों (इन्पुट्स) में कमी करके उत्पादक के लाभ के मार्जिन को बढ़ाना, आर्थिक कार्य-कुशलता के रूप में लिया जाता है।

आर्थिक वृद्धि (Economic Growth)

वह दर जिस पर एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है और इसे सामान्यतया 'जीडीपी' या 'जीएनपी' या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का एक पक्ष है। एक देश भले एक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर आर्थिक रूप से वृद्धि प्राप्त कर सकता है लेकिन गुणवत्ता में परिवर्तन (सुधार) हुए बिना उसे आर्थिक रूप से विकसित नहीं कहा जाएगा।

आर्थिक सूचक (Economic Indicator)

वह सांख्यिक सूचना जो यह प्रदर्शित करती है कि एक देश की अर्थव्यवस्था का कार्य-निष्पादन अल्प व दीर्घकाल में कैसा रहा है (जिसे बेरोजगारी दर या विदेशी व्यापार जैसे कारकों के साथ जोड़कर देखा जाता है।

पैमाने की बचतें (Economies of Scale)

जब उत्पादन की मात्रा अधिक हो तो प्रत्येक ईकाई की औसत लागत कम हो जाती है (क्योंकि जहां परिवर्तनशील कारकों की लागतें उत्पादन की मात्रा अनुसार बदलती रहती हैं, स्थिर लागतें अपरिवर्तित रहती है भले उत्पादन का स्तर कुछ भी हो।)

असामान्य मद (Extraordinary Item)

लाभ या हानि जो उन घटनाओं या लेनदेनों से उत्पन्न होती है जो प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों से भिन्न होते हैं। और जो महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ ऐसी प्रकृति के होते हैं जिनकी बार-बार या नियमित रूप से होने की आशा नहीं की जा सकती। इसमें वे महत्वपूर्ण समायोजन भी सम्मिलित होते हैं जो परिस्थितिवंश आवश्यक होते और वे भले गत अवधियों से सम्बन्धित हों लेकिन उनका निर्धारण वर्तमान अवधि में किया जाता है।

अंतर्जात वृद्धि (Endogenous Growth)

यह सिद्धान्त बताता है कि दीर्घवधि में आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय प्रणाली के अन्तर्गत कारकों द्वारा ही संचालित होती है, न कि इसके बाहर के कारकों द्वारा।

राष्ट्रीय आय का सन्तुलन स्तर (Equilibrium Level of National Income)

राष्ट्रीय आय का वह स्तर जब उसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, यानि जब उपभोग व्यय और उत्पादन दोनों समान होते हैं।

सन्तुलित कीमत (Equilibrium Price)

वह कीमत जिस पर आपूर्ति और मांग दोनों की मात्रा समान होती है ताकि आपूर्त्ति या मांग में से कोई भी अधिक नहीं होती है।

प्रभावी मांग (Effective Demand)

जब उपभोक्ता वस्तु या सेवा को ग्रहण करने की इच्छा रखता है, और उसमें उसे खरीदने की योग्यता या क्षमता होती है, ऐसी मांग को प्रभावी मांग कहा जाता है।

सुविधा-अधिकार (Easement)

वह अधिकार जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति (जैसे भूमि) को विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकता है।

कार्य-कुशलता (Efficiency)

इस बात की तुलना कि उन्हीं संसाधनों (जैसे धन, समय, श्रम आदि) के प्रयोग द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है और वास्तव में प्राप्त या उत्पादित होता है। इसके लिए सामान्यतया एक मानक निर्धारित किया जाता है और कार्य-निष्पादन उससे मापा जाता है। यह उत्पादकता के निर्धारण का महत्वपूर्ण कारक है।

प्रभावी प्राप्ति (Effective Yield)

जब एक निवेश किया जाता है तो उस पर प्रतिलाभ (रिटर्न) का वादा या आशा होती है लेकिन यह प्रतिलाभ वास्तव में उतना न होकर कम या ज्यादा होता है। यही वास्तविक प्रतिलाभ (रिटर्न) प्रभावी प्राप्ति (ईल्ड) है।

कार्य-कुशलता मजदूरी (Efficiency Wages)

सामान्यतया बाजार में कार्य के लिए मजदूरी की एक दर होती है और जब व्यक्ति को काम पर लगाया जाता है तो उसे वह मजदूरी दर दी जाती है। उस व्यक्ति में अधिक या और अच्छा कार्य करने की क्षमता या योग्यता हो सकती है और वह ऐसा तभी करता है जब उसे बाजार दर से अधिक मजदूरी की पेशकश की जाती है। यही अधिक मजदूरी कार्य-कुशलता मजदूरी है।

वाह्य शेष (External Balance)

वह स्थिति जब एक देश के लोग दूसरे देशों में उतना ही निवेश करते हैं जितना कि दूसरे

देशों के लोग इस देश में निवेश करते हैं। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की वृद्धि और कम विदेशी ऋण इसी के अनुसार होते हैं।

वाह्य ऋण (External Debt)

देश का वह ऋण जो विदेशी ऋणदाताओं से लिया गया है। इन ऋणदाताओं में विदेशी वाणिज्यिक बैंक, विदेशी सरकारें, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान सम्मिलित होते हैं। ये ऋण जिस मुद्रा में लिये जाते हैं उनका ब्याज के साथ वापसी भुगतान उसी मुद्रा में किया जाता है।

वाह्य घाटा (External Deficit)

देश के भुगतान शेष के घाटे को वाह्य घाटा कहा जाता है।

वाह्य वृद्धि (External Growth)

जब एक फर्म अपनी बिक्रियां या उत्पादन बढ़ाती है तो उसके कारोबार में वृद्धि होती है लेकिन उसे वाह्य वृद्धि नहीं कहा जा सकता। वह तभी होती है जब वह अन्य कम्पनियां खरीद कर कारोबार को बढ़ाती है।

विशिष्ट क्षेत्र (Eminent Domain)

सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोग के लिए सम्पत्ति (जैसे कि भूमि) के अधिग्रहण की शक्ति। भूमि जैसे मामलों में सम्पत्ति को इसके मालिकों से स्वेच्छिक लेनदेन की तरह नहीं खरीदा जा सकता बल्कि उसे एक उचित प्रतिपूर्त्ति देकर ही खरीदा जाता है जो आमतौर पर न्यायालय की कारवाई के तहत (खरीदते समय बाजार मूल्य के आधार पर) निर्धारित किया जाता है।

भार (Encumbrance)

निधियों का वह आरक्षण जो खरीद आर्डरों, अनुबंधों या वेतन वचनबद्धताओं के लिए देय तो है लेकिन उनका अभी भुगतान नहीं किया गया है और इनका भुगतान एक विशेष विनियोजन खाते में से किया जाना है।

समानता (Equalization)

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक उपयुक्त सरकारी निकाय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके क्षेत्राधिकार में सभी सम्पत्तियों का निर्धारण एक समान स्तर पर किया जाए ।

इक्विटी प्राप्ति दर (Equity Yield Rate)

इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल (रिटर्न) की अपेक्षित दर। इसकी गणना आवधिक नकदी प्रवाह (ऋण सेवा के भुगतान के बाद लेकिन करों के भुगतान से पूर्व) को इक्विटी में निवेश द्वारा भाग करके की जाती है।

समान मूल्यांकन (Equalized Valuations)

एक निश्चित कर योग्य तिथि को समस्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन (अनुमान)।

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)

विदेशी मुद्रा की वह सीमा जो देश के भीतर और घरेलू मुद्रा की वह सीमा जो देश के बाहर ले जायी जा सकती है विनिमय नियंत्रण में निर्धारित होती है।

विनिमय दर (Exchange Rate)

एक देश की मुद्रा की वह कीमत जो अन्य देश की मुद्रा में बतायी जाती है। दूसरे शब्दों में वह दर जिस पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विनिमय हो सकता है। उदाहरणतया, यूरो व येन दो मुद्राओं में यदि एक यूरो की विनिमय दर एक येन की तुलना में जितनी अधिक होगी एक येन की एक यूरो की तुलना में उतनी ही कम होगी।

व्यय (Expenditure)

आस्तियों, वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से दायित्व ग्रहण करना, नकदी का संवितरण या सम्पत्ति का हस्तांतरण व्यय की श्रेणी में आता है।

प्रत्याशित प्रतिफल (Expected Return)

निवेशक निवेश करते समय आय के साथ जिस पूँजी लाभ की आशा करता है। वह प्रत्याशित प्रतिफल (रिटर्न) कहलाता है।

आर्थिक प्रकार की नीति (Expansory Policy)

मौद्रिक प्राधिकारियों की नीति कि धन का प्रसार कर आर्थिक गतिविधि को तेज किया जाए। ऐसा वे मुख्यतया ब्याज दरें घटकार करते हैं ताकि कम्पनियां, व्यक्ति व बैंक अधिक से अधिक ऋण ले सकें।

आर्थिक उत्पादन (Economic Output)

आर्थिक उत्पाद समस्त वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री के मूल्य का माप करता है। दूसरे शब्दों में चूंकि यह अन्तिम खरीददारी और मध्यवर्ती निविष्टियों (इन्पुट्स) का योग है अतः इसमें मध्यवर्ती खरीद की दोहरी गणना होती है।

F

वित्तीयन (Financing)

वे साधन जिनके द्वारा एक सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करती है या बचत के बजट से उत्पन्न वित्तीय संसाधनों को आबंटित करती है।

राजकोषीय वर्ष (Fiscal Year)

बारह माह की अवधि जिस पर करों की गणना की जाती है।

कारक लागत (Factor Cost)

उत्पादन के सभी कारकों की, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यमी जिन्हें वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, कुल लागत।

उत्पादन के कारक (Factors of Production)

आर्थिक गतिविधि की निविष्टियां (इन्पुट्स) जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम जिन्हें आर्थिक लाभ के लिए वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

राजकोषीय वाधा (Fiscal Drag)

सरकार के कर-राजस्व पर मुद्रास्फीति का प्रभाव।

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

वह नीति जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए सरकारी व्यय और कराधान से सम्बधित है।

वित्तीय लिखत (Financial Instrument)

एक वित्तीय आस्ति का स्वामित्व प्रमाणपत्र, जैसे कि एक बांड या एक शेयर।

वित्तीय विवरण (Financial Statement)

एक विशेष तिथि, प्रायः वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि को, एक समुदाय (या प्रतिष्ठान) की आस्तियों और दायित्वों की प्रस्तुति।

सुलभ वस्तु (Free Good)

ऐसी वस्तु जो आपूर्ति में भरपूर हो और उसकी कीमत नाममात्र हो।

स्थिर आस्तियां (Fixed Assets)

दीर्घकालिक मूर्त्त आस्तियां, जैसे कि भवन, उपस्कर और भूमि, जिन्हें विगत लेनदेनों या परिस्थितियों के फलस्वरूप प्राप्त या नियंत्रित किया गया है।

स्थिर परिचालनगत व्यय (Fixed Operating Expenses)

व्यवसाय करने की वे लागतें जो कब्जा या उत्पादन करने से परिवर्तित नहीं होती और उनका भुगतान तब भी किया जाता है भले सम्पत्ति अधिकृत (कब्जे में) है या खाली और इसी तरह उत्पादन अधिक या कम या बिल्कुल नहीं हो रहा है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार के खर्च की तुलना में गैर-उधारी प्राप्तियां कम होती है और उस कमी को सरकार जनता से उधार लेकर पूरा करती है। गैर-उधारी प्राप्तियों से कुल व्यय जितना अधिक होता है उस राजकोषीय घाटा कहते हैं।

कल्पित आस्तियां (Fictitious Assets)

तुलनपत्र के आस्तियां पक्ष में वह मद जिसका कोई वास्तविक मूल्य न हो (उदाहरणतया, लाभ-हानि विवरण में नामे शेष)।

वित्त विधेयक (Finance Bill)

वित्त विधेयक वह विधेयक (बिल) है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वित्त प्रस्ताव किये जाते हैं और उसमें वह विधेयक भी सम्मिलित होता है जो एक अवधि के लिए पूरक वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावी बनाता है।

चूंकि इस वित्त विधेयक में कर प्रस्ताव भी होते हैं अतः अनुदानों की मांगों पर मत देने और व्यय की जानकारी होने पर लोक सभा में इस पर विचार किया जाता और पारित किया जाता।

जो पहले आया, वह पहले जाएगा (फीफो) (FIFO)

एक अवधि में जैसे-जैसे मदें ग्रहण की जाती हैं उन्हें उसी क्रम में बेचा या प्रयोग (उपभोग) में लाया जाता है। बेची या उपभोग की गयी मदों की लागत की गणना भी उसी क्रम में की जाती है।

स्थिर लागत (Fixed Cost)

ऐसी उत्पादन लागत जो एक समय अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा से निरपेक्ष या अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए, कार्यालय-भवन का किराया, कार्यालयीन कर्मचारियों का वेतन, ऋणों पर ब्याज आदि, जिनका उत्पादन होने या न होने या उत्पादन की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

निधि (Fund)

एक विशेष गतिविधि के संचालन या एक विशेष प्रयोजन के लिए रखी गयी राशि जो निर्धारित विशिष्ट विनियमों, प्रतिबंधों और सीमाओं द्वारा संचालित की जाती है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) (Foreign Direct Investment) (FDI)

विदेश मे निगमित एक कम्पनी भारत में स्थापित अपनी शाखा या अनुषंगी (सहायक) कम्पनी के माध्यम से जब निवेश करती है तब ऐसा निवेश 'एफडीआई' कहलाता है।

निधिशेष (Fund Balance)

एक सरकारी निधि की आस्तियों एवं दायित्वों में जब अन्तर रिपोर्ट किया जाता है तो उसे निधि शेष कहा जाता। इसे 'निधि इक्विटी' के नाम से भी जाना जाता है।

विदेशी संस्थागत निवेश (एफ आई आई) (Foreign Institutional Investment) (FII)

भारत से बाहर विदेश में स्थापित संस्थान जब भारत में निवेश करना चाहता है तब ऐसा निवेश 'एफ आई आई' कहलाता है।

आधारभूत लेखा अवधारणाएँ (Fundamental Accounting Assumptions)

वे आधारभूत लेखा अवधारणाएं जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने को रेखांकित करती हैं, वे हैं चलायमान समनुत्थान, क्रमबद्धता (या एकरूपता) और प्रोद्भवन। सामान्यतया, इनका विशेष रूप से उल्लेख नही किया जाता है क्योंकि यह

माना जाता है कि उनकी स्वीकृति और प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि उनका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसका प्रकटन करना आवश्यक है।

उत्पादन के कारक (Factors of Production)

यह वह आर्थिक शब्दावली है जो आर्थिक लाभ कमाने के प्रयास में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त निविष्टियों के प्रयोग का वर्णन करती है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम सम्मिलित हैं, यही निविष्टियां (इन्पुट्स) उत्पादन के कारक हैं।

G

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (Gross Domestic Product (GDP))

यह उस आर्थिक क्रिया का व्यापक माप है जो एक देश में एक अवधि में होती है। यह देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसकी गणना मूल्य वर्धित आधार पर की जाती है। एक उत्पादक प्रतिष्ठान का अंशदान अन्तिम वस्तुओं के मूल्य और प्रयुक्त कच्चे माल की लागत के अन्तर द्वारा ज्ञात किया जाता है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय उत्पाद् सभी उत्पादक प्रतिष्ठानों के कुल मूल्य का योग है। अधिक स्पष्ट रूप से

$$\text{जीडीपी} = C + I + G + (x - m)$$

इसमें C= उपभोग है जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर उपभोक्ताओं द्वारा व्यय है।

I = सकल प्राइवेट घरेलु निवेश जो कारोबारी प्रतिष्ठानों द्वारा नई पूंजीगत वस्तुओं (जैसेकि संयंत्र व मशीनरी) और माल सूची (इन्वेंट्री) में वृद्धि और कारखानों, मकानों आदि का निर्माण आदि को प्रदर्शित करता है।

G = सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय।

x – m = वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात (s) और आयात (m) का अन्तर है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) (Gross National Product (GNP))

एक देश में दिये गये वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मित तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाज़ार मूल्य तथा स्थानीय लोगों द्वारा विदेश में किये गये निवेश से अर्जित आय, इनके

योग में से विदेशियों द्वारा घरेलू बाज़ार में अर्जित आय को घटाने के बाद जो राशि बचती है वह देश का 'जीएनपी' है।

अपस्फीतिकारी जीडीपी (GDP Deflator)

वह राशि जिस तक एक देश की 'जीडीपी' मुद्रा-स्फीति को हिसाब में लेने के बाद कम हो जाती है।

सामान्य सन्तुलन (General Equilibrium)

बाज़ार की ऐसी स्थिति जब सभी निर्णायकों (क्रेताओं और विक्रेताओं) की मांग व पूर्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और न तो कोई अधिकता होती है और न ही कोई कमी, तब ऐसी स्थिति को अर्थशास्त्र में सामान्य सन्तुलन कहते हैं।

सामान्य खाता-बही (लैजर) (General Ledger)

लेखाकार की मौलिक प्रविष्टि का रिकार्ड जो कि सरकार की समस्त वित्तीय गतिविधि की 'पेपर ट्रेल' बनाने में महत्वपूर्ण है।

वस्तुएं एवं सेवाएं कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST))

'जीएसटी' एक व्यापक मूल्यवर्धक कर(वैल्यू ऐडड टैक्स) है जो वस्तुओं व सेवाओं पर लगाया जाता है। 'जीएसटी' पद्धति में वस्तुओं व सेवाओं में भेद नहीं किया जाता है क्योंकि वे आपूर्ति श्रृंखला से गुजरती हैं। 'जीएसटी' आयात, वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को प्रदान करने सहित वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेनदेनों पर लगाया जाता है। यह खरीद या बिक्री या ऋणतंत्र युक्त आपूर्ति के प्रत्येक स्तर पर मूल्य वर्धित पर लगाया जाता है। सभी कारोबारों को कर-तंत्र से होकर गुजरना पड़ता है। और कर का बोझ अन्तिम ग्राहक पर पड़ता है।

वैश्विक जमा रसीद (जीडीआर) (Global Depository Receipt)-GDR

ऐसी रसीद जो विदेश-आधारित निगमीय शेयरों के स्वामित्व को प्रकट करती है और इसका लेन-देन (ट्रेडिंग) विश्व भर के अनेक पूंजी बाज़ारों में होता है। इन 'जीडीआर' की कीमतें आमतौर पर सन्निहित शेयरों के मूल्य के आसपास ही होती हैं।

'जीएनपी' अपस्फीतिकारी (GNP Deflator)

वह राशि जिस तक एक देश का 'जीएनपी' मुद्रास्फीति को हिसाब में लेने से कम हो जाता है।

सरकारी व्यय (Government Expenditure)

इसके अन्तर्गत नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण सहित सरकार द्वारा किया जाने वाला समस्त व्यय आता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय शामिल होता है और इसका निधिकरण (फंडिंग) कर-राजस्व द्वारा किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities)

उधार लेने के लिए सरकार बांडों, नोटों और अन्य ऋण लिखतों का विक्रय करती है। सामान्यतया, ये लिखतें दीर्घावधि प्रतिभूतियां होती हैं और इनकी मार्किट रेटिंग सबसे अधिक होती है।

सामान्य बाध्यता बांड (General Obligation Bond)

यह एक प्रकार का म्युनिसिपल बांड होता है जिसका मूलधन व ब्याज जारीकर्ता द्वारा पूरी निष्ठा व साख द्वारा सुरक्षित रखा जाता हैं और आमतौर पर इसकी गारंटी या तो जारीकर्ता द्वारा असीमित या फिर सीमित कर भुगतान शक्ति (अधिकार) द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के बांडों को सामान्यतया स्थानीय सरकारें जारी करती हैं और ये आमतौर पर शहरी मूलभूत ढांचे के वित्तपोषण के प्रयोजन से जारी किये जाते हैं।

सहायता अनुदान (Grant in Aid)

ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां जो राज्य सरकार के लिए इसलिए आवश्यक हैं ताकि वे ऐसी विकास की स्कीमों की लागत को पूरा कर सके जो उसने भारत सरकार के अनुमोदन पर चलायी हैं और उनका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना है या फिर कुछ ऐसे इलाकों का विकास करना है जो अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े हैं और विकास के बाद वे अन्य के समान हो जाएंगे।

सरकारी खाते (Government Accounts)

सरकारी खाते 3 भागों में रखे जाते हैं

1 भारत की संचित निधियां
2 भारत की आकास्मिक निधियां
3 सार्वजनिक खाता

सरकारी बांड (Government Bonds)

सरकार द्वारा जारी ऋण (डेट) प्रतिभूति ताकि सरकारी व्यय को सहायता मिले। अधिकांशतया इसे देश की घरेलू मुद्रा में ही जारी किया जाता है। सरकारी ऋण वह ऋण है जिसका भुगतान सरकार के किसी भी स्तर से किया जाएगा और इसे सरकार के पूर्ण विश्वास का समर्थन प्राप्त होता है।

सरकारी लेखा मानक बोर्ड (Government Accounting Standards Board) (GASB)

राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों हेतु अन्तिम प्राधिकारी निर्धारक निकाय।

सरकारी लेखा-मानक परामर्श बोर्ड (जीएएसएबी) (Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB)

इस बोर्ड की स्थापना 'कैग' द्वारा 2002 में की गई थी ताकि सार्वजनिक वित्त में उभरती नई प्राथमिकताओं की पूर्ति की जा सके। बोर्ड (जीएएसएबी) का गठन इसलिए किया गया था ताकि वह सरकारी लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों का निर्माण करे और उनमें सुधार लाए ताकि जवाबदेही तंत्र में वृद्धि की जाए।

अनुदान (Grants)

विशेष परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए प्रेषित राशि और उपहार या सामान्य बजट सहायता सहित सरकार के अन्य स्तरों, या प्राइवेट व्यक्तियों या संस्थाओं से प्राप्त समस्त गैर-वापसी योग्य अन्तरण।

H

उच्च मुद्रास्फीति (Hyper Inflation)

अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। लोगों की नज़र में पैसे का कोई मूल्य नहीं रह जाता और उसके लिए उनका आकर्षण बिल्कुल नहीं रह जाता। जिन लोगों की आय कमोवेश स्थिर हो, वे तो आर्थिक रूप से खस्ताहाल में आ जाते हैं। राजनैतिक व सामाजिक स्थिति में भारी उथल-पुथल होने लगती है। उदाहरण के लिए, जर्मन में ऐसी स्थिति वर्ष 1918 से 1923 के बीच रही थी। वर्ष 1923 के अकेले एक माह में मुद्रास्फीति की दर 2500% नोट की गई थी।

प्राक्कल्पना (Hypothesis)

किसी घटना या गतिविधि की व्याख्या के लिए जब किसी बात को मान लिया जाता है और आगे की जांच के लिए कोई दिशा-निर्देश दिया जाता है। एक प्राक्कल्पना सही या गलत साबित हो सकती है। उसका खंडन किया जा सकता है। यदि तथ्यों के आधार पर उसका खंडन न हो तो उसे सत्यापित करने या उसकी पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता है।

दुर्लभ-मुद्रा (Hard Currency)

एक ऐसी मुद्रा जिसे दुनिया के अनेक भागों में वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए बड़े स्तर पर स्वीकार किया जाता है, उसे दुर्लभ मुद्रा माना जाता है। अल्पकाल में यह मुद्रा अन्य मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहती है। विदेशी मुद्रा बाज़ार में यह उच्च रूप से तरल होती है। यू एस डालर और ब्रिटिश पाउन्ड दुर्लभ मुद्राओं के अच्छे उदाहरण हैं।

हवाला (Hawala)

धन के स्थानान्तरण (ट्रांसफर) की एक परम्परागत प्रणाली जिसमें धन एक एजेंट को अदा किया जाता है और वह उस देश या एरिया में, जिसमें पैसा भेजा जाना है, अपने साथी को हिदायत देता है कि वह उस अन्तिम व्यक्ति को उतनी राशि का भुगतान कर दे। इस तरह पैसे का अन्तरण किसी बैंकिंग प्रणाली से बाहर होता है और दोनों देशों की सरकारें इस लेन-देन से बेखबर रहती हैं।

समस्तरीय इक्विटी (Horizontal Equity)

समस्तरीय इक्विटी का अर्थ है कि एक स्थिति में सभी लोगों पर एक-ही नीति का प्रयोग। कर उगाही बिल्कुल इसी वित्तीय मापदंड पर आधारित है। उदाहरण स्वरूप, एक स्थान पर दो व्यक्ति 25000 रुपये वार्षिक कमाते हैं। अतः दोनों ही इस राशि पर समान कर अदा करेंगे।

I

माल-सूची (Inventory)

मूर्त सम्पत्ति जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के लिए धारित की गयी है या बिक्री के

लिए उत्पादन की प्रक्रिया में है, या बिक्री के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपभोग के लिए, जिनमें रखरखाव की आपूर्ति और उपयोग्य वस्तुएं तो शामिल हैं लेकिन मशीनरी और स्पेयर्स नहीं।

आयात (Imports)

विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।

निवेश (Investment)

उन आस्तियों पर व्यय जिन्हें ब्याज, आय, लाभ या अन्य फायदों के अर्जन (कमाने) के लिए धारित किया जाता है।

करों का प्रभाव (Incidence of Taxes)

जब, एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति अन्ततः कर का बोझ उठाते हैं उस या उनपर कर का प्रभाव आपूर्त्ति और मांग की कीमत-लोच से सम्बन्धित है। उदाहरणस्वरूप यदि सरकार यह निर्णय लेती हैं कि सिगरेटों पर कर बढ़ा दिया जाए जिनकी मांग काफी लोच-रहित है तो उत्पादक बिक्री कीमत को करों की पूरी राशि तक बढ़ा सकते हैं। यदि कीमतें बढ़ने पर भी उतनी ही सिगरटें खरीदी जाती हैं तो यह कहा जाता है कि करों का प्रभाव पूरी तरह से क्रेताओं पर पड़ा है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)

जब कर उपभोक्ता या अर्जक की आय पर न लगाकर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कर का बोझ उत्पाद के विभिन्न स्तरों पर अन्तरित कर दिया जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, वैट और सर्विस टैक्स।

आन्तरिक लेखा-परीक्षा (Internal Audit)

आन्तरिक लेखा-परीक्षा एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूरक आश्वासन और परामर्शदायीं गतिविधि है जो संगठन के परिचालनों को मूल्य-वार्धित बनाने और उनमें सुधार लाने के लिए डिजाइन की गयी है। यह जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार लाने और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणालीगत व अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। यह संगठन को अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है।

आन्तरिक लेखा-परीक्षा एक संगठन की प्रभावशीलता व कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अन्तदृष्टि देने और सिफारिशें करने में महत्वपूर्ण है। यह आंकड़ों और कारोबार की प्रक्रियाओं के विश्लेषण और मूल्यांकन पर आधारित है।

आय दृष्टिकोण (Income Approach)

वह विधि जिसके द्वारा सम्पत्तियों के बाज़ार मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है जो सम्पत्ति के भविष्य में प्रत्याशित निवल आय को वर्तमान मूल्य (जिसे कभी-कभी पूंजीगत मूल्य भी कहा जाता है) से माप करता है।

क्षतिग्रस्तता हानि (Impairment Loss)

एक आस्ति के अधिक वर्णित अंकित मूल्य को ह्रासित करने के लिए एक विशेष अनावर्ति प्रभार। सामान्यतया, एक आस्ति को तब मूल्य-क्षतिग्रस्त माना जाता है जब उसका अंकित मूल्य (बुक वैल्यु) उस राशि से अधिक हो जाता है जो आस्ति के प्रयोग से भावी निवल नकदी प्रवाह के रूप में प्रत्याशित है। अतः क्षतिग्रस्तता मूल्यह्रास अधिक अंकित मूल्य को कम करके उचित मूल्य के समान ला देता है।

अप्रत्यक्ष लागत (Indirect Cost)

एक सेवा प्रदायी प्रतिष्ठान के परिचालन बजट में सेवा की वे लागतें जो प्रदर्शित नहीं होती हैं। अप्रत्यक्ष लागत का उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है जब एक जल प्रदाय सेवा की अप्रत्यक्ष लागत वह है जो गैर-जल विभाग के कर्मचारियों द्वारा पानी के बिलों को तैयार करने के लिए समय लगाया जाता है। सेवा देने की कुल लागत का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार की लागतों का विश्लेषण करना आवश्यक है। अप्रत्यक्ष लागतों का मामला ज्यादातर प्रतिष्ठान निधियों के संदर्भ में आता है।

मुद्रास्फीति (Inflation)

वह प्रक्रिसा जो कीमतों के स्तर में निरन्तर और सामान्य वृद्धि करती है। इसे आमतौर पर खुदरा मूल्य सूचकांक को विनिमय की वार्षिक दर से मापा जाता है।

मुद्रास्फीतिकारी अन्तर (Inflationary Gap)

वह स्थिति जब मांग उत्पादन के स्तर से अधिक हो जाती है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव है और इससे कीमतों के बढ़ने का दबाब बनता है।

मुद्रास्फीतिकारी चक्र (Inflationary Spiral)

ऐसी स्थिति जब कीमतों में वृद्धि अधिक मजदूरी की मांग को प्रोत्साहित करती है और उसका असर फिर कीमतों में वृद्धि पर पड़ता है।

मुद्रास्फीति कर (Inflation Tax)

एक प्रकार का कर जिसके द्वारा सरकार धन की आपूर्ति को परिवर्तित करती है। जब धन की आपूर्ति बढ़ती है तो वर्तमान धन का मूल्य घटता है, अतः सरकार धन रखने वालों पर इस प्रकार का कर लगाती है।

अन्तर-सरकार राजस्व (Inter Government Revenues)

जब सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच निधियों का आदान-प्रदान होता है जो सामान्यतया संघीय सरकार और राज्य सरकारों और इसी तरह राज्य सरकार व स्थानीय सरकार (निकाय) के बीच होता है।

ब्याज (Interest)

वह प्रतिपूर्ति जो धन के प्रयोग के लिए की गयी है या की जाने वाली है। इसमें वह राशियां की सम्मिलित हैं जो आवधिक आधार पर देय हैं या जब ऋण दिया जाता है तब डिस्कांउंट की जाती हैं। म्यूनिस्पल बांडों के मामले में ब्याज भुगतान दैनिक आधार पर उपचित होता है लेकिन उसका भुगतान छमाही आधार पर किया जाता है।

ब्याज-दर (Interest Rate)

देय ब्याज मूल राशि एक समय तक के प्रयोग के लिए प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है। इसे हमेशा वार्षिक आधार पर व्यक्त किया जाता है।

L

स्वतःगामी अर्थव्यवस्था (Laissez-Fair Economy)

जहां सरकार अर्थव्यवस्था के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि वह मानती है कि यह उचित है कि अर्थव्यवस्था को स्वंय चलने दिया जाए।

श्रमिक गहन (Labour Intensive)

पूंजी गहन (Capital Internsive) के विपरीत, यह वह उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें श्रम उत्पादन'कारक का बहुल प्रयोग किया जाता है जैसे कि भारत में कृषि कार्य।

भूमि (Land)

अर्थशास्त्र में, उत्पादन कारक के रूप में भूमि से अभिप्रायः भूमि के उपरी भाग, प्राकृतिक संसाधनों और उन प्राकृतिक उत्पादन शक्तियों से है जिन्हें मनुष्य नियंत्रित करता है। कानून में, इसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है कि पृथ्वी के एक सतही भाग, उसके नीचे और वे सभी चीज जो प्रकृति या मनुष्य द्वारा सम्बद्ध की गयी हैं, भूमि ही है।

'लाफर' वक्र (Laffer Curve)

यह वक्र कर दरों के आपसी सम्बन्ध और उससे कर राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करती है। यह वक्र स्पष्ट करती है कि जैसे जैसे निम्न स्तरों से कर बढ़ते हैं सरकार द्वारा संगहीत कर राजस्व भी वैसे-वैसे ही बढ़ता है। यह यह भी स्पष्ट करती है कि कर दरों में वृद्धि जब एक निश्चित बिन्दु से आगे होने लगती है तो लोग मेहनत से कार्य करना बन्द कर देते हैं या कार्य करना ही छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में कर-राजस्व कम होना शुरू हो जाता है। अन्ततः जब कर दरें 100% पर पहुंच जाती है तो लोग कार्य न करना ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि वे जो भी कमाएंगे सारा सरकार को कर के रूप में चला जाएगा।

वसूली (Levy)

एक प्रकार का कर या अर्थदंड (जुर्माना) लगाना।

लाइसेंस व परमिट (Licenses and Permits)

कारोबार और अन्य गतिविधियों के संचालन को विनियमित करने के लिए देश द्वारा जारी दस्तावेज। भोजन की बिक्री के लाइसेंसों या भवन के परमिटों के मामलों में लाइसेंस या परमिट जारी करने के साथ निरीक्षण भी किया जा सकता है। सामान्यतया, लाइसेंस या परमिट जारी करने के साथ फीस (शुल्क) भी ली जाती है ताकि सम्बंधित लागत को अंशतः या पूरी तरह से कवर किया जा सके।

रेखीय-मद बजट (Line-Item Budget)

एक कार्यक्रम बजट के विपरीत, रेखीय-मद बजट वह बजट है जो व्यय को श्रेणियों या मदों के विस्तार, जैसे कि आपूर्तियां, उपस्कर, रखरखाव या वेतन के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

दीर्घावधि ऋण (Long Term Debt)

एक दिये गये समय पर वे सामुदायिक उधार या ऋण के बकाया शेष जिन्हें 12 माह या इससे अधिक समय के बाद वापस किया जाना है।

एकमुश्त कर (Lump Sum Tax)

यह वह कर है जो व्यक्ति की आय से सम्बद्ध नहीं है कि वह कितना कमाता है।

M

सीमान्त आय (Marginal Income)

एक अधिक ईकाई के उत्पादन से लाभ में वृद्धि।

मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

सरकार की धन आपूर्ति, बैंक दरों और उधार (ऋण) विषयक नीति।

बाजार कीमत (Market Price)

वह कीमत जिसे एक क्रेता और विक्रेता एक लेन-देन पर देने और लेने के लिए सहमत होते हैं और वास्तव में वह राशि अदा की जाती है।

परिपक्वता तिथि (Maturity Date)

वह तिथि जिस पर बांड या ऋण (डेट) का मूल धन पूरी तरह से देय है।

समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics)

समग्र अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली के व्यवहार का अध्ययन, न कि व्यक्तिगत लोगों, फर्मों या बाज़ारों का (क्योंकि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र यानि माइक्रोइकानामिक्स का अध्ययन क्षेत्र है)। समष्टि अर्थशास्त्र (माइक्रोइकनामिक्स) का सम्बन्ध मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय की भविष्यवाणी से है जो मुख्य आर्थिक कारकों के विश्लेषण से किया

जाता है। यह विश्लेषण भविष्यवाणी करने योग्य तरीके और प्रवृत्तियों तथा उनका एक-दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हें प्रदर्शित करता है।

प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (Marginal Rate of Substitution)

अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (MRS) वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की एक ईकाई को दूसरी वस्तु की एक ईकाई के स्थान पर छोड़ने को तैयार होता है बशर्ते प्रतिस्थापन से पूर्व और बाद उपयोगिता (Utility) का स्तर वही रहता हो। उपभोग स्तरों पर हमारी प्रतिस्थापना की सीमान्त दरें एक-समान रहती हैं।

'एक क्रेता-बहुल विक्रेता' बाजार (Monopsony)

यह वह बाज़ार व्यवस्था है जिसमें एक क्रेता और बहुल विक्रेता होते हैं यानि बाजार दर पर क्रेता का अधिक प्रभाव होता है।

गुणक (Multiplier)

एक आर्थिक मॉडल में गुणक वह संख्या है जो एक आर्थिक मात्रा और दूसरी आर्थिक मात्रा के परस्पर सम्बंध की मात्रात्मक व्याख्या करती है।

एकाधिकारिक प्रतियोगिता (Monopolistic Competition)

बाज़ार की वह संरचना जिसमें अनेक या बहुत विक्रेता होते हैं और वे एक जैसी मगर कुछ भिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद की कीमत व मात्रा इस प्रकार निर्धारित कर सकता है कि समग्र बाज़ार की स्थिति में कोई भी परिवर्तन न हो।

बाज़ार पूंजीकरण (Market Capitalization)

एक कम्पनी के शेयरों के बाजार मूल्य की गणना एक शेयर के अंकित बाज़ार मूल्य के बकाया कुल शेयरों की संख्या से गुणा करके की जाती है। इसे 'मार्किट कैंप' भी कहा जाता है।

एम 1 (M1)

यह भारत में धन के स्टाक का एक माप है जिसे 'संकीर्ण धन' भी कहा जाता है। इसमें बैंकों के निवल मांग जमा राशियां, भारतीय, रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां और जनता के पास करंसी नोट व सिक्के सम्मिलित होते हैं। 'निबल मांग जमा राशियों' में चालू खातों की जमा राशियां और बचत जमा राशियों का वह भाग जो मांग दायित्व

के रूप में है और लोगों के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियां वे निधियां हैं जो कुछ संस्थानों, जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि, विदेशी सरकारों और केन्द्रीय बैंकों के पास हैं।

एम 2 (M2)

इसमें एम 1 के अलावा डाक घर बचत बैंक की जमा राशियां आती हैं।

एम 3 (M3)

एम 3 = सरकार को निबल बैंक ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण + बैंकिंग क्षेत्र की निबल विदेशी मुद्रा आस्तियां + लोगों के सरकारी मुद्रा दायित्व - बैंकिंग क्षेत्र के निबल गैर-मौद्रिक दायित्व (सावाधि जमा राशियों को छोड़कर)।

एम 4 (M4)

एम 3 का योग और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) को घटाकर समस्त डाकघर जमाराशियां।

मुद्रिकृत घाटा (Monetised Deficit)

जब राजकोषीय घाटे की राशि का वित्तपोषण (पूर्ति) मुद्रा छाप कर की जाती है।

मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश का मौद्रिक प्राधिकरण धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसके लिए वह प्रायः आर्थिक प्रगति और स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज-दर को लक्ष्य बनाता है। लक्ष्यों में सामान्यतया अपेक्षया अधिक स्थायी कीमतें व कम बेरोजगारी भी सम्मिलित रहते हैं। मौद्रिक सिद्धान्त उपयुक्त मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं। यह विस्तृत या संकुचित हो सकती है। एक विस्तृत मौद्रिक नीति में धन का कुल प्रसार सामान्य से अधिक तीव्र और संकुचित मौद्रिक नीति में सामान्य से कम तीव्र होता है और यहां तक कि इसे कम भी कर दिया जाता है। परम्परागत रूप से मंदी की स्थिति में बेरोजगारी को दूर करने के लिए विस्तृत मौद्रिक नीति का प्रयोग करते हुए ब्याज दरों में कटौती की जाती है इस आशा के साथ कि सस्ता कर्ज होने से कारोबारी अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। संकुचित मौद्रिक नीति का उद्देश्य यह रहता है कि मुद्रास्फीति को कम किया जाए ताकि आस्ति के मूल्य में गिरावट व विकार को रोका जा सके।

सीमान्त कर दर (Marginal Tax Rate)

प्रत्येक अतिरिक्त कर योग्य आय के रुपये पर अतिरिक्त कर दायित्व

सीमान्त उपयोगिता का सिद्धान्त (Marginal Utility Theory)

उपभोक्ता अपने बजट को आबंटन इस प्रकार करते हैं कि उनका कल्याण अधिकतम हो। वह तभी होगा जब प्रत्येक रुपये की सीमान्त उपयोगिता खरीदी गयी सभी वस्तुओं में एक समान हो।

मनीलांड्रिग (Money Laundering)

वह प्रक्रिया जहां गैर कानूनी तरीके से पैसा (धन) प्राप्त कर अर्थव्यवस्था में परिचालित (सर्कुलेट) किया जाता है और उसे ऐसा रूप दिया जाता है कि मानो वह विधि सम्मत स्रोत से प्राप्त किया गया है।

सीमान्त लागत (Marginal Cost)

उत्पादन की एक और ईकाई बढ़ाने की लागत।

सीमान्त राजस्व (Marginal Revenue)

एक और ईकाई की बिक्री से प्राप्त राजस्व।

सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)

यह सिद्धान्त इस बात की जांच करता है कि एक वस्तु का अतिरिक्त ईकाई के उपभोग की संतुष्टि में क्या वृद्धि हुई है। यह सन्तुष्टि के अधिकतम स्तर का निर्धारण करता है और यह तभी हो सकता है जब सीमान्त उपयोगिता (MU) = कीमत (P)। जब कीमत सीमान्त उपयोगिता से अधिक रहती है उपभोक्ता अतिरिक्त ईकाई की खरीद नहीं करेगा। उदाहरण के रूप में जब केक की कीमत 50 पैसे हो तो उस पर 75 पैसे देने का कोई आधार नहीं है।

उपयोगी (मेरिट) वस्तुएं (Merit Goods)

सरकार सम्पूर्ण समाज के फायदे के लिए इस प्रकार की चीजों (जैसे कि शिक्षा, टीके आदि) को निःशुल्क (मुफ्त) प्रदान करती हैं क्योंकि यदि इन्हें बाज़ार शक्तियों या प्राइवेट (निजी) प्रतिष्ठानों पर छोड़ दिया जाए तो वे लोगों की आवश्यकतानुसार प्रदान नहीं करेंगे।

एकाधिकार (Monopoly)

बाज़ार की वह स्थिति (या प्रकार) जहां उत्पादक एक ही हो या कुछ उत्पादकों का समूह हो और उनमें एकजुटता हो और वे वस्तु की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं और इस कारण वस्तु की कीमत सामान्य से कुछ अधिक ही होती है। इस प्रकार के बाज़ार में नयी फर्मों का प्रवेश या तो बन्द होता है या फिर प्रतिबंधित।

म्यूनिस्पल बांड (Municipal Bonds)

स्थानीय सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा जारी किये गये बांड जो जारीकर्ता निकाय के लिए एक ऋण (डेट) बाध्यता है। ये बांड दो प्रकार के होते हैं अर्थात् सामान्य बाध्यकारी बांड और राजस्व बांड।

N

राष्ट्रीय ऋण (National Debt)

सरकार द्वारा लिया गया ऋण जिसका अभी भुगतान किया जाना है।

स्वाभाविक एकाधिकार (Natural Monopoly)

एकाधिकार की वह प्रकार है जो एक विशेष उद्योग के कारोबार में उच्च स्थिर लागतों या प्रारम्भिक लागतों के परिणामस्वरूप विद्यमान होती हैं। क्योंकि यह आर्थिक रूप से उचित है कि कुछ स्वाभाविक एकाधिकार हों, सरकारें परिचालन में इन्हें प्रायः इस प्रकार विनियमित करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो।

राष्ट्रीय आय (National Income)

यह एक देश के एक निश्चित समय की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निवल जोड़ है यानि मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज और राष्ट्र के अन्दर लोगों के पेंशन के भुगतान का कुल जोड़ है।

राष्ट्रीय आय खाते (National Income Accounts)

राष्ट्रीय आय खाते एक वर्ष के दौरान घरेलू व निर्यात किये गये दोनों की उत्पादित व बिक्री की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रदर्शित करते हैं। वे जी.डी.पी. व जी.एन.

पी दोनों को कवर करने के साथ-साथ उस आय को भी सम्मिलित करते हैं जो विदेशों में निवेश से प्राप्त होती है।

निवल आय (Net Income)

अनुमत्य व्यय को घटाने के बाद सम्पत्ति से प्रत्याशित आय।

निवल परिचालनगत आय (Net Operating Income)

परिचालन व्यय को घटाने के बाद, लेकिन आयकर और ब्याज की कटौती से पूर्व एक कम्पनी की परिचालनगत आय। यदि यह राशि घनात्मक (+) मूल्य में है तो इसे निवल परिचालगत आय कहा जाता है, लेकिन यदि यह ऋणात्मक (–) मूल्य में है तो इसे निवल परिचालनगत हानि कहा जाएगा।

निवल वर्तमान मूल्य (Net Present Value)

एक निवेश प्रस्ताव की अर्थ-सुलभता (Viability) के मूल्यांकन का कटौती के बाद नकदी प्रवाह का माप। यह निश्चित करता है कि क्या प्रत्याशित मापी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य परियोजना पर निवेश से अधिक है या नहीं। निवल वर्तमान मूल्य कटौती के बाद नकद अन्तर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह (प्रारम्भिक व्यय सहित) का अन्तर है।

निवल ऋण (Net Lending)

राष्ट्रीय सरकार द्वारा सरकार के वर्ष के दौरान गारंटीशुदा नियंत्रित ऋण की चुकौती (सर्विसिंग) के लिए अग्रिम, इस प्रकार के ऋणों की वापसी अदायगी के बाद शेष। इनमें ऋण व्यय या वे कार्यक्रम ऋण भी शामिल हैं जो सरकारी निगमों को पुनः दिये गये हैं।

निवल आस्तियां (Net Assets)

एक प्रतिष्ठान के दायित्वों से अधिक आस्तियों (कल्पित आस्तियों को छोड़कर) के अंकित मूल्य से ऊपर। इसे निवल मूल्य (नेट वर्थ) या शेयर धारकों की निधियां भी कहा जाता है।

निवल लाभ (Net Benefit)

एक विशेष लेखा अवधि के दौरान व्यय से अधिक राजस्व (आय)। जब इस गणना का परिणाम ऋणात्मक (–) हो तो इसे निवल हानि (Net loss) कहा जाता है। निवल लाभ को कर से पूर्व और कर के बाद दिखाया जा सकता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य (Net Realisable Value)

यह वह मूल्य है जो कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में एक आस्ति की वास्तविक प्राक्कलित विक्रय कीमत होती है और इसमें से आस्ति के पूर्ण करने की लागत और इसे बिक्री योग्य बनाने के लिए आवश्यक लागत घटायी जाती है।

गैर-योजनागत व्यय (Non-Plan Expenditure)

इसमें सरकारों का राजस्व और पूंजीगत व्यय सम्मलित है जो ब्याज भुगतानों, रक्षा व्यय, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) डाक घाटा, पुलिस व्यय, पेंशन-भुगतान, आर्थिक सेवाएं, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को ऋण, राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों व विदेशी सरकारों को ऋण व अनुदान से सम्बन्धित हैं।

निवल घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product)

एक देश में उत्पादित सभी उत्पादों व सेवाओं का मूल्य जिसमें से उनके उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी का मूल्य घटाया जाएगा।

गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)

अनिवार्य कर वसूली से भिन्न स्रोतों से संग्रहीत राजस्व जिसमें वह राजस्व भी सम्मिलित है जो जनता को सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गयी प्रत्यक्ष सेवा के बदले या जो सरकार की नियामक व निवेश गतिविधियों द्वारा संग्रहीत किया गया है।

गैर-अपवादता (Non-Excludability)

उस वस्तु का उपभोग गैर अपवादस्वरूप है जब वह बहुत ही मंहगी है या लोगों को उसके उपभोग से रोका नहीं जा सकता।

गैर-गारंटी बांड या राजस्व बांड (Non-Guaranteed Bonds or Revenue Bonds)

केवल विशेष स्रोत से प्राप्त राजस्व को ही निवेशकों को ब्याज या मूलधन के भुगतान के लिए गिरवी रखा जा सकता है।

नाममात्र आय (Nominal Income)

वह आय जिसमें मुद्रा-स्फीति और घटती क्रय शक्ति को समायोजित नहीं किया गया है।

गैर-विकासात्मक व्यय (Non-Developmental Expenditure)

उपभोग की प्रकृति का व्यय, जैसेकि रक्षा व्यय, ब्याज-भुगतान, कानून व व्यवस्था

सम्बंधी व्यय, लोक प्रशासन, कोई उत्पादक आस्ति का सृजन नहीं करता है और न ही सरकार को कोई आय या प्रतिफल प्रदान करता है। इस कारण ऐसे व्यय को गैर विकासात्मक व्यय कहा जाता है। यह विकासात्मक व्यय का विलोमार्थी है।

O

मुक्त अर्थव्यवस्था (Open Economy)

जो अर्थव्यवस्था वाणिज्यिक लेन-देन के लिए शेष दुनिया के लिए खुली है उसे मुक्त अर्थव्यवसाि कहा जाता है।

वैकल्पिक लागत (Opportunity Cost)

वैकल्पिक लागत वह लागत है जो एक वस्तु को छोड़ने पर विकल्प के रूप में दूसरी को ग्रहण करने के लिए खर्च की जाती है।

परिचालनात्मक व्यय (Operating Expenses)

ऐसे व्यय जो संगठन के दिन-व-दिन की गतिविधियों के संचालन के लिए खर्च होते हैं और वे प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से सम्बन्धित नहीं हैं। परिचालानात्मक व्यय में पे-रोल, बिक्री कमीशन, कर्मचारी लाभ व पेंशन अंशदान, परिवहन व यात्रा व्यय, ऋण परिशोधन व मूल्यह्रास, किराया, मरम्मत व कर आदि सम्मिलित हैं।

स्वातिमत्व (Ownership)

जब संपत्ति के उपयोग का अधिकार किसी के पास हो और अन्य को नहीं।

अप्रचलन (Obsolescence)

एक आस्ति के मूल्य में इस कारण गिरावट होना कि वह अप्रचलित हो गयी है या फिर प्रोद्योगिकी परिवर्तनों, उत्पादन विधियों में सुधार, उत्पादन के लिए बाज़ार की मांग में परिवर्तन या आस्ति की सेवा देने में कमी आ जाने या कानूनी अथवा अन्य प्रतिबंधों के लागू होने से कम उपयोगी हो गयी है।

P

'पेरेटो दक्षता' (Pareto Efficiency)

वह आर्थिक स्थिति जब संसाधनों का आबंटन बहुत ही दक्षतापूर्ण किया जाता है । पेरेटो दक्षता तब प्राप्त होती है जब एक ऐसी वितरण रणनीति हो कि एक पार्टी की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक दूसरी पार्टी की स्थिति न बिगड़े। पेरेटो दक्षता का आशय समता या औचित्य से नहीं है।

गत अवधि की मद (Prior Period Item)

गत एक या अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों के तैयार करने में त्रुटियों या भूलचूकों के परिणामस्वरूप चालू आवधियों में उत्पन्न कोई बड़ा प्रभार या ऋण।

अंशतः छूट (Partial Exemption)

जब किसी अन्यथा कर योग्य निर्धारित मूल्य की राशि के कर दायित्व को संवैधानिक और/अथवा सांविधिक कार्रवाई द्वारा हटाया जाता है।

पेरेटो सुधार (Pareto Improvement)

संसाधनों का पुनराबंटन कुछ इस तरह से कि एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाना, बिना दूसरे की स्थिति बिगाड़कर।

कार्य-निष्पादन बजट (Performance Budget)

कार्य-निष्पादन बजट प्रक्रिया को सामान्यतया एक ऐसी प्रणाली द्वारा समझा जाता है जो सार्वजनिक (लोक) व्यय के कार्यों, कार्यक्रमों, कार्य-निष्पादन, ईकाइयां जैसेकि गतिविधियां/परियोजना आदि के संदर्भ में प्रस्तुत करती है। जो सरकार के उत्पादन (Output) और इसकी लागत को मुख्यतया प्रदर्शित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकार के सभी परिचालनों को कार्यों, कार्यक्रमों व गतिविधियों द्वारा वर्गीकृत करके प्रस्तुत करती है।

प्रावधान (Provision)

एक राशि को बट्टेखाते डालना या आस्तियों को मूल्य में कमी या मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान करते हुए जारी रखना या फिर किसी ऐसे खाते दायित्व के लिए प्रावधान करते हुए जारी रखना जिसकी राशि का निर्धारण अधिक यथार्थता (ठीक-ठीक) से नहीं किया

जा सकता। दूसरे शब्दों में, इसका माप बहुत हद तक अनुमान द्वारा ही किया जा सकता है।

स्थायी ऋण (Permanent Debt)

एक समुदाय द्वारा उधार लेना जिसके ऋण को विशेषरूप से वापस अदा भी करना है।

आनुपातिक कराधान (Proportional Taxation)

जब कर का बोझ आय के सभी स्तरों पर समान हो।

सार्वजनिक वस्तु (Public Good)

एक समुदाय एक वस्तु का उपभोग सामूहिक रूप से करता है, यानि उसमें जब कुछ लोग उपयोग करते हैं तो वे दूसरों को रोकते नहीं हैं।

सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी (Public Private Partnerships)

सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जब सरकार व निजी क्षेत्र (कम्पनियां आदि) का संयुक्त उद्यम हो। राष्ट्रीय खातों में इन दोनों का वर्गीकरण किया जा सकता है और यह स्पष्ट किया जा सकता है कि दोनों में से किसका शेयर ज्यादा होगा यानि सरकार का या निजी क्षेत्र का।

फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)

जब एक ग्राफिक वक्र द्वारा मजदूरी और बेरोजगारी की दर का सम्बंध एक बाज़ार अर्थव्यवस्था में प्रदर्शित किया जाता है।

निजी वस्तु (Private Good)

एक वस्तु जिसका भुगतान अवश्य किया जाना है और जैसे-जैसे इसका उपभोग होता जाता है, आपूर्ति कम कर दी जाती है।

कर की प्रवृत्ति (Propensity to Tax)

राष्ट्रीय आय और कर के बीच अनुपात।

प्रगतिशील कर संरचना (Progressive Tax Structure)

एक ऐसी कर संरचना जिसमें जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है सीमान्त कर दर (MTR) भी बढ़ती जाती है।

सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

राष्ट्रीय ऋण और अन्य ऋण जिनके लिए केन्द्रीय सरकार अन्ततः उत्तरदायी है, जैसाकि राष्ट्रीयकृत उद्योगों के ऋण।

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

जो व्यय सरकार द्वारा अपने रखरखाव के साथ-साथ समाज के निमित्त और कल्याण और समग्र अर्थव्यवस्था पर खर्च किया जाता है वह सार्वजनिक व्यय कहलाता है। इसमें सार्वजनिक प्राधिकरणों, केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय सरकारों के वे व्यय भी शामिल हैं जो नागरिकों के बचाव, उनके आर्थिक व सामाजिक कल्याण पर खर्च होते हैं।

सार्वजनिक खर्च (Public Spending)

सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किया जाने वाला खर्च।

सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं (Public Utilities)

कम्पनियां (जैसे बिजली, गैस या ट्रांसपोर्ट) जो सेवाएं देती हैं और जिन्हें समस्त समुदाय उपयोग करता है।

उच्चतम दर (Peak Rate)

एक मद पर लागू सीमा-शुल्क की उच्चतम दर।

कार्य निष्पादन लेखा-परीक्षा (Performance Audit)

कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा सरकार द्वारा वित्तपोषित संगठनों की स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया है। चूंकि इन निधियों का सरोकार जनता से है अतः यह लेखा परीक्षा यह जांच करती है कि सरकार की इन निधियों के उपयोग की क्या दक्षता व प्रभावशीलता है। यह मूल्यांकन सामाजिक व वित्तीय दोनों दृष्टियों से किया जाता है। इस जांच से संरचित और व्यावसायिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है।

योजनागत व्यय (Plan Expenditure)

सरकार के खाते में से जब केन्द्रीय योजना के लिए पैसा (धन) दिया जाता है उसे योजनागत व्यय कहा जाता है। इसमें राजस्व व्यय और पूंजी व्यय और राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता सम्मिलित होती है।

सार्वजनिक वित्त (Public Finance)

अर्थशास्त्र की वह शाखा जो सरकार के वित्त पर चर्चा करती है। इसमें कराधान, सरकार के बजट और इसके व्यय और इस सभी का मुद्रा बाजार और सामान्य अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सरकार के पास जो पैसा है उसका वह किस दक्षता के साथ उपयोग करती है और वह नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या उपाय करती है और उसके तौर तरीकों में सुधार की क्या आवश्यकताएं व संभावनाएं हैं। सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की प्राचीनतम शाखाओं में से एक है।

योजनागत परिव्यय (Plan Outlay)

योजना में परियोजनाओं स्कीमों और कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय की राशि की घोषणा की जाती है। योजना के परिव्यय के धन को बजटीय समर्थन और आन्तरिक व अतिरिक्त बजटीय संसाधनों द्वारा जुटाया जाता है। बजटीय समर्थन को सरकारी खातों में योजनागत व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

प्रारम्भिक घाटा (Primary Deficit)

राजकोषीय घाटा में से ब्याज का भुगतान घटाना। यह प्रकट करता है कि सरकार की उधारी पहले लिये गये ऋणों को ब्याज भुगतान को छोड़कर व्ययों को किस हद तक पूरा कर रही है।

प्रगतिशील कर (Progressive Tax)

वह कर है जिसे अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कर चुकाता है।

सरकारी खाता (Public Account)

सरकारी खाते का गठन भारत के संविधान की धारा 266(2) के अधीन हुआ था। इसमें वे लेनदेन आते हैं जो भारत की संचित निधि में सम्मिलित ऋणों से भिन्न ऋणों के हैं। इस भाग में ऋणों जमा राशियों व अग्रिमों के वे लेन देन हैं जिनके सम्बंध में सरकार का दायित्व है कि वह प्राप्त धन का वापसी भुगतान अथवा किये गये भुगतान पर कोई वापसी का दावा बनता है तो उसकी वसूली करे। धन-प्रेषण व उक्त की प्रविष्टियों को यथाशीघ्र सम्बन्धित शीर्षों में समायोजित करना आवश्यक है। चूंकि सरकारी खाते की

प्राप्तियां सरकार की सामान्य प्राप्तियां नहीं होती हैं अतः इस खाते के भुगतानों पर संसद की अनुमति/मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

R

मंदी (Recession)

व्यापार चक्र की वह अवधि जिसमें कार्य करने वालों और मशीनरी की अस्थायी बेरोजगारी की स्थिति होती है। परम्परागत रूप से इस काल में कीमत व मजदूरी भी घटती है। जब मंदी की स्थिति कुछ वर्षों की बजाय अधिक हो जाती है तो उसे 'डिप्रेशन' कहा जाता है।

मंदी का अन्तर (Recessionary GAP)

वह मात्रा जब सन्तुलित जीडीपी पूर्ण रोजगार युक्त 'जीडीपी' से कम हो। इसके परिणामस्वरूप, कीमतें घटने लगती हैं और इस समस्या से निपटाने के लिए सरकार राजकोषीय उपाय करती है।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

यह निवेश में निर्णय लेने में अनिश्चितता को स्वीकार करने या उसे कम करने, पता लगाने व विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। जब एक निवेशक या निधि प्रबंधक किसी भी समय विश्लेषण करता है और निवेश में संभावित जोखिम का आकलन करता है तथा उचित कार्रवाई करता है (या नहीं भी करता है) ताकि उसके निवेश लक्ष्य की पूर्ति हो और इसमें वह कितना जोखिम ले। जब जोखिम प्रबंधन अपर्याप्त हो तो व्यक्तियों और कम्पनियों दोनों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

'रेपो' दर (Repo Rate)

वह दर जिस पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यह यू एस के 'डिस्काउन्ट रेट' की तरह हैं। यह मौद्रिक नीति का एक साधन है। जब बैंकों के पास निधियों (धन) की कमी हो जाती है तो वे इस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। जब यह दर कम होती है तो बैंकों को सस्ती दर पर और जब दर अधिक होती है तो मंहगी दर पर उधार मिलता है। कम दर पर निधियां उपलब्ध होने पर बैंक उद्योगों को सस्ती दर पर ऋण दे सकते हैं।

'रिवर्स रेपो' दर (Reverse Repo Rate)

यह 'रेपो रेट' का विपरीत मौद्रिक साधन है। जब बैंकों को पास अस्थायी तरलता बढ जाती है तो वह अधिक तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं और उन्हें उस पर 'रिवर्स रेपो' दर पर ब्याज मिलता है। बैंक अतिरिक्त तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करें या किसी अन्य निवेश विकल्प में रखें, यह प्राप्य प्रतिफल पर निर्भर करता है। जब रिवर्स रेपो दर अधिक होगी, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास तरलता रखेंगे और यदि कम होगी तो किसी अन्य निवेश विकल्प में जाने के लिए विचार करेंगे जहां उन्हें बेहतर प्रतिफल (रिटर्न) उपलब्ध होता हो।

धन जुटाना और उसका विनियोजन (Raise and Appropriate)

यह वाक्य किसी एक व्यय या अनेक व्ययों की पूर्ति के लिए निधि स्रोत का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानि व्यय की पूर्ति कर वसूली (टैक्स लेवी) द्वारा की जाए या किन्ही अन्य स्थानीय प्राप्तियों से।

धन की आपूर्ति बढ़ाना (रिफ्लेट) (Reflate)

देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए देश के लोग जिस धन का अर्जन करते और उसे खर्च करते है उसकी मात्रा बढ़ाना। एक तरह से अपमुद्रास्फीति का सामना धन की आपूर्ति बढ़ाकर करना है जिसे ब्याज दरें घटाकर और सरकारी व्यय बढ़ाकर किया जाता है।

धन की आपूर्ति में वृद्धि (रिफलेशन) (Reflation)

अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाकर और कर कम करके चुस्त करना।

धन आपूर्ति की वृद्धि की नीति (Reflationary Policy)

वह नीति जो आर्थिक गतिविधि को गतिशील (या चुस्त) बनाती है जिसे राजकोषीय तरीके से यानि कर के स्तरों को घटाकर या मौद्रिक तरीके से यानि सरकारी व्यय में वृद्धि करके किया जा सकता है।

प्रत्यावर्ती कर (Regressive Tax)

कर की वह प्रणाली जिसमें औसत कर को घटाकर लोगों की आय में वृद्धि करना।

'रियल टर्म' आंकड़े (Real Term Figures)

सामान्य कीमत वृद्धि के प्रभाव को समायोजित करने की राशियां जिन्हें जीडीपी बाजार कीमत 'डिफलेटर' द्वारा मापा जाता है। यह वर्षों के दौरान किये गये व्यय की कीमतों के परिवर्तन से बिना किसी हानि के तुलना को सक्षम बनाता है।

क्षेत्रीय नीति (Regional Policy)

केन्द्र सरकार की वह नीति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास से जुड़ी होती है। सरकार यह आशा करती है कि इससे सभी क्षेत्रों का समुचित विकास होगा और विशेषकर उन पिछड़े क्षेत्रों का जो विकास से बंचित है और उनका जीवन स्तर बहुत कम है।

आरक्षित मुद्रा (Reserve Currency)

अन्तरराष्ट्रीय वित्त में प्रयुक्त मजबूत मुद्रा जो अन्य देशों द्वारा अपनी कमजोर मुद्राओं के समर्थन के लिए रखी जाती है।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से बढ़ जाता है।

राजस्व बजट (Revenue Budget)

सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के प्रस्ताव।

संशोधित प्राक्कलन (Revised Estimates)

गत बजट के प्राक्कलन और वास्तविक व्यय जिसे आमतौर पर अगले बजट में प्रस्तुत किया जाता है।

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

वह व्यय जो आस्ति सृजन में प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें वह धन आता है जो सरकार के विभागों के सामान्य संचालन और अन्य सेवाओं, जैसेकि सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर ब्याज, पर खर्च होता है।

राजस्व प्राप्ति (Revenue Receipt)

इसमें सरकार द्वारा कर संग्रहण और अन्य प्राप्ति की वे राशियां सम्मिलित हैं जो सरकार

द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज व किये गये निवेशों पर लाभांश और उसके द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं की फीस व अन्य प्राप्तियां के रूप में प्राप्त होती हैं।

राजस्व बेशी (Revenue Surplus)

राजस्व व्यय से अधिक की राजस्व प्राप्तियां राजस्व बेशी कहलाती हैं। राजस्व प्राप्तियों में वे राशियां शामिल होती हैं जो सभी परिचालनों के द्वारा कारोबार धन को रूप में प्राप्त करता है जबकि राजस्व व्यय में वे राशियां सम्मिलित होती हैं जो कि दैनिक संचालन पर खर्च होती हैं।

राजस्व बांड (Revenue Bonds)

एक प्रकार के बांड जो कि उत्पादक प्रतिष्ठान के राजस्व वित्त पोषण के लिए जारी किये जाते हैं। इनका ब्याज के लाभ भुगतान प्रतिष्ठान की अर्जन आय और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त किया जाता है। म्युनिस्पल बांड के रूप में होते हैं जो जल आपूर्ति, मल व्ययन (सीवर), कूड़ा-करकट प्रबंधन प्रणाली सहित मूलभूत ढांचे के विकास के लिए वित्त पोषण के रूप में जारी किये जाते हैं।

पैमाने की बचतें (Returns to Scale)

पैमाने की बचतें एक फर्म के उत्पादन कार्य से उत्पन्न होती हैं। ये दीर्घकाल में उत्पादन में वृद्धि और निविष्टियों (उत्पादन के कारकों) में वृद्धि के संदर्भ में व्यवहार पर चर्चा करती हैं। यानि, जैसे-जैसे उत्पादन के कारकों में वृद्धि की जाती है तो उसका उत्पादन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है।

राजस्व (Revenue)

वे सभी निधियां जो एक देश को करों, विशेष सेवाओं की फीस अन्य सरकारों से प्राप्त राशियां, अर्थदंड (जुर्माने), जब्तियां, शेयर आधारित राजस्व और अन्य ब्याज स्वरूप आय के रूप में प्राप्त होती हैं।

नियंत्रित मुद्रास्फीति (Repressed Inflation)

अन्तर्हित मुद्रास्फीति के दबाबों को हटाये बिना प्रत्यक्ष नियंत्रक उपायों द्वारा मुद्रास्फीति के दबाब को रोकना। वास्तविक मुद्रास्फीति बाजार दबाबों के फलस्वरूप बनती है। जब मुद्रास्फीति लम्बे समय तक विद्यमान रहती है तो इससे वस्तुओं की आपूर्ति मंद पड़ जाती है और काला बाज़ारी और जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है।

S

बिक्री कर (Sales Tax)

खुदरा बिक्रियों पर प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला कर।

लाभ-हानि विवरण (Statement of Profit & Loss)

वह विवरण जो एक ओर प्रतिष्ठान के लेखा-वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों और दूसरी ओर व्यय स्वरूप भुगतानों को प्रदर्शित करता है। जब प्राप्तियां भुगतानों से अधिक होती हैं तो लाभ और जब भुगतान राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो हानि की स्थिति होती है। इस कारण इसे लाभ-हानि विवरण कहा जाता है।

मुद्रास्फीति-जनित मंदी (Stagflation)

वह स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति की दर ऊंची और आर्थिक प्रगति की दर नीचे हो और बेरोजगारी का स्तर निरन्तर रूप से ऊपर ही रहता है। इससे आर्थिक नीति में एक विडम्बना की स्थिति बनी रहती है कि जिन कार्यों से मुद्रास्फीति की दर को कम या बेरोजगारी को कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है वे वास्तव में आर्थिक प्रगति को और ज्यादा खराब बना देते हैं।

सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) (Statutory Liquidity Ratio (SLR))

यह शब्दावली बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है जो यह प्रकट करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को जमा राशियों का एक न्यूनतम प्रतिशत सोना, नकद रूप से या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अपेक्षित है। यह प्रतिशत 'एसएलआर' कहलाती है।

अल्पावधि ऋण (Short Term Debt)

12 माह या कम की परिपक्वता वाले ऋणों का एक तिथि को बकाया शेष।

सीधी रेखा विधि (Straight Line Method)

मूल्यह्रास की वह विधि जिसमें किसी आस्ति के मूल्यह्रास प्रभार की गणना उसके आस्ति के कुल प्रत्याशित उपयोगी जीवन के वर्षों द्वारा मूल्यह्रास योग्य राशि को भाग देकर की जाती है।

प्रकीर्ण देनदार (Sundry Debtors)

वे व्यक्ति जिन्हें वस्तुएं बेची गयी हैं या सेवाएं दी गयी हैं या फिर अनुबंधात्मक बाध्यताओं के लिए उनसे राशियां प्राप्य हैं। इन व्यक्तियों को देनदार, व्यापार देनदार, लेखा प्राप्य भी कहते हैं जिनके समूह को तुलनपत्र में प्रकीर्ण देनदार कहा जाता है।

विशेष प्रयोजन यंत्र (एसपीवी) (Special Purpose Vehicle (SPV))

आमतौर पर यह एक प्रतिष्ठान की एक प्रकार की एक अनुषंगी कम्पनी हैं जिसकी अपनी एक आस्ति/दायित्व संरचना है और कानूनी स्थिति है जो इसकी बाध्यताओं को सुरक्षित करती हैं चाहे मूल प्रतिष्ठान दिवालिया भी क्यों न हो जाए। 'एसपीजी' का मुख्य उद्देश्य इसे अपने मूल प्रतिष्ठान से अलग आस्तित्व देना है।

सुदृढ़िकरण कार्य (Stabilization Function)

आर्थिक गतिविधि पर सरकार का समग्र प्रभाव।

अधिभार (Surcharge)

पहले से ही विद्यमान प्रभार (चार्ज), जैसे कर, फीस, अर्थदण्ड (जुर्माना) या आस्ति में अतिरिक्त प्रभार जोड़ना।

वेशी राजस्व (Surplus Revenue)

वह राशि जिससे राजस्व-आस्तियां जैसे नकदी, प्राप्य राशियां और अन्य आस्तियां दायित्वों व प्रारक्षित निधियों से अधिक होती है।

प्रतिभूतियां लेनदेन कर (एसटीटी) (Securities Transaction Tax (STT)

यह शेयरों, म्यूचल फंडों की यूनिटों के लेनदेन पर लागू होता है। 2004-05 के बजट से शुरू यह कर उस अर्जित लाभ कर को प्रतिस्थापित करता है जो उन शेयरों की बिक्री पर लगता था जिन्हें एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए धारित किया जाता था। (इसे दीर्घवधि पूंजीगत लाभ कर भी कहा जाता था)।

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) (Special Drawing Right (SDR))

अनेक राष्ट्रीय मुद्राओं पर आधारित एक कृत्रिम मुद्रा ईकाई। 'एसडीआर' अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष सहित अनेक अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के लिए एक आधिकारिक मौद्रिक ईकाई का कार्य करता है और राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के लिए पूरक प्रारक्षित निधि के रूप में

कार्य करता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के सदस्य अन्य देशों के साथ अपने व्यापार शेष का 'आई एम एफ' को भुगतान 'एस डी आर' द्वारा कर सकते हैं। जब एक देश द्वारा दूसरे देश को कोई भुगतान करना है तो वह अपनी मुद्रा में न करके 'एस डी आर' के माध्यम से करता है और 'एस डी आर' ग्रहण करने के लिए उसे अपनी मुद्रा देनी होगी।

सुलभ मुद्रा (Soft Currency)

सुलभ या सस्ती मुद्रा दुर्लभ (महंगी) मुद्रा (Hard Currency) की ही विलोभ मुद्रा है। सुलभ या सस्ती मुद्रा वह है जो बहुत बुरी तरह बदलती रहती है या अन्य मुद्राओं के झुकाव से काफी गिरती भी है।

आर्थिक सहायता (Subsidy)

सरकार द्वारा व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को एक लाभ देना जो नकद रूप से भुगतान करके या करों में छूट देकर दी जाती है। आर्थिक सहायता (सब्सिडी) एक प्रकार के बोझ को घटाने और जनहित में दी जाती है।

T

कर आधार (Tax Basis)

वित्त के संदर्भ में एक आस्ति की मूल लागत में से मूल्यह्रास घटाने के बाद जो राशि शेष रहती है उसे कर के प्रयोजनों के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

कर परिवर्तन (Tax Shifting)

जब कर तो एक व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन उसे अदा दूसरा व्यक्ति करता है, इसे कर का अन्तरण या कर-परिवर्तन कहते हैं।

अस्थायी ऋण (Temporary Debt)

जब एक समुदाय नोट (हुंडियों) के रूप में उधार लेता है और उसकी अवधि एक वर्ष या कम की होती है।

व्यापार घाटा (Trade Deficit)

ऐसी स्थिति जब देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो यानि वह उतनी विदेशी मुद्रा अर्जित (कमाता) नहीं करता है जितनी कि उसका भुगतान करता है।

संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था (Transition Economy)

जब अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से आयोजित से मुक्त बाजार व्यवस्था की ओर बदलती या परिवर्तित होती तो यह परिवर्तन के दौरान की अर्थ व्यवस्था परिवर्तनशील या संमक्रणकालीन अर्थव्यवस्था कहलाती है।

प्रसार (Trickle-Down)

एक आर्थिक सिद्धान्त कि जब अर्थव्यवस्था की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव से समाज के सबसे ज्यादा गरीब लोगों की अपेक्षया अधिक मदद होती है, बजाय इसके कि सरकार उन्हें सीधे कल्याण के नाम से कोई भुगतान करे।

प्रशुल्क (Tariff)

जब आयात पर कोई कर या शुल्क लगाया जाता है जो भौतिक ईकाइयों जैसे कि टन के अनुसार (विशिष्ट) या मूल्य के अनुसार (Advalorem) लगाया जा सकता है। यह शुल्क कई कारणें से लगाया जा सकता है जिनमें सरकारी राजस्व को बढ़ाना, घरेलू उद्योग का संरक्षण, घरेलू रोज़गार में वृद्धि या फिर भुगतान शेष के घाटे को कम करना शामिल है। राजस्व बढ़ने के साथ-साथ प्रशुल्क बढ़ाने के कुछ नुकसान भी हैं, इनसे व्यापार की मात्रा कम हो जाती है, उपभोक्ताओं को वस्तु का दाम अधिक चुकाना पड़ता है, निर्यातकों का मार्जिन घट जाता है जब उन्हें आयात के पश्चात् वस्तु का निर्माण कर निर्यात करना होता है।

कर प्रत्याशी हुंडियां (Tax Anticipation Notes)

ये वे नोट (हुंडियां) होती हैं जिन्हें राज्य सरकारें या म्यूनिस्पल निकाय कर-राजस्व प्राप्त करने से पूर्व चालू परिचालनों को वित्त पोषित करने के लिए जारी करते हैं। जब जारीकर्ता सरकार या निकाय कर प्राप्त करता है तो उसका प्रयोग ऋण भुगतान में किया जाता है।

कर प्रभाव (Tax Incidence)

यह एक कर लगाने से आर्थिक कल्याण के वितरण पर होने वाले असर का विश्लेषण है। इसका प्रभाव उसी समुदाय पर पड़ता है जो कर का बोझ अन्ततः वहन करता है।

टर्नओवर कर (Turnover Tax)

कुल खरीद-बिक्री कर (टर्नओवर टैक्स) बिक्री कर या वैट (Value Added Tax) की तरह ही होता है। अन्तर यह है कि कुल खरीद-बिक्री कर मध्यवर्ती और संभवतया पूंजीगत वस्तुओं पर लगता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो विशिष्ट रूप से मूल्यानुसार (Ad Valorem) लगाया जाता है और यह उत्पादन प्रक्रिया या स्तर पर लागू होता है।

उछाल कर (Tax Buoyancy)

यह वह सूचक है जो 'जीडीपी' या राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अनुरूप राजस्व संग्रहण की दक्षता और प्रमाण का माप करता है। उछाल कर तब लगाया जाता है जब राजस्व की वृद्धि राष्ट्रीय आय या उत्पाद से कहीं ज्यादा अनुपात में होती है।

U

अप्रत्याशित मुद्रास्फीति (Unanticipated Inflation)

जब मुद्रास्फीति साल-दर-साल घटती-बढ़ती (अस्थिर) रहती है तब व्यक्तियों और व्यवसायिओं को भविष्य में इसकी दर का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। अप्रत्याशित मुद्रास्फीति तब होती है जब आर्थिक-एजेंट (लोग, व्यवसाय और सरकारें) मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने में त्रुटियां करते हैं।

संघीय उत्पाद शुल्क (Union Excise Duty)

देश में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क।

V

मूल्य-वर्धित कर (Value Added Tax)

'वैट' वह कर है जो एक फर्म के उत्पाद के मूल्य-वर्धन पर प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। जैसे-जैसे उत्पाद उत्पादन के भिन्न-भिन्न स्तरों से गुजरता है उस पर बार-बार

कर से बचने के लिए उस पर एक ही बार कर लगाया जाता है। यह कर उत्पाद के उत्पादन (आउटपुट) के मूल्य और उसकी निविष्टि (इन्पुट) के मूल्य के अन्तर पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पाद की उत्पादन निविष्टियों (इन्पुट्स) पर कर लगाना है।

उर्ध्वगामी इक्विटी (Vertical Equity)

इससे यह आशय है कि जिन लोगों के पास अधिक धन-सम्पत्ति (Wealth) है वे ज्यादा कर दें। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में धन-सम्पत्ति का अधिक प्रगामी रूप से पुनर्वितरण हो। यह व्यक्ति की आय की बजाय धन-सम्पत्ति और अन्य कारकों के आधार पर लागू किया जाता है।

लेखानुदान पर मत (Vote on Account)

एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, सरकार इस बात के लिए फिकरमंद रहती है कि संसद को बजट के प्रावधानों और कराधान के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के लिए पूरा अवसर दिया जाए। चूंकि संसद पूरे बजट पर नये वित्त वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व मत (वोट) देने में असमर्थ है अतः देश का प्रशासन चलाने और हाथ में पर्याप्त पैसा रखने के लिए विशेष प्रावधान द्वारा सरकार संसद में लेखानुदान पर (Vote on Account) लेती है ताकि वर्ष के शेष भाग के दौरान विभिन्न मदों पर खर्च के लिए उसके पास हाथ में पर्याप्त धन हो।

W

कार्यशील पूंजी (Working Capital)

एक प्रतिष्ठान के दैनिक परिचालनों के संचालन के लिए उपलब्ध निधियां। इस अल्पकालिक ऋणों सहित चालू दायित्वों से अधिक चालू आस्तियां के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।

अपेक्षित वृद्धि दर (Warranted Growth Rate)

एक प्रतिष्ठान के दैनिक परिचालनों के संचालन के लिए उपलब्ध निधियां। इसे अल्पावधि ऋणों सहित चालू दायित्वों से अधिक चालू आस्तियों के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि लोग अपनी आय का 90% खर्च कर 10% बचाते

हैं और अर्थवयवस्था की उत्पादन के लिए पूंजी अनुपात 4 है तो अर्थव्यवस्था की वांछित वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत (यानि 10 प्रतिशत को 4 से भाग देकर) होगी। यह वह वृद्धि दर है जिस पर उत्पादन के लिए पूंजी का अनुपात 4 पर स्थिर रहेगा।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics)

अर्थशास्त्र की वह शाखा जो आर्थिक दक्षता की परिभाषा के साथ-साथ संसाधनों के आबंटन का विश्लेषण करे और इस विश्लेषण से कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जो व्यक्ति व समाज के कल्याण के लिए हितकर हों। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की खोज इटली के इंजीनियर और समाजशास्त्री विलफ्रेडो पेरेटो ने की थी जिसने यह निष्कर्ष निकाला था कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में कीमत प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति की उपयोगिता (Utility) को अधिकतम स्तर तक पहुंचा सकता है। कल्याणकारी के सिद्धान्तवादियों ने इस सिद्धान्त को मानते हुए लागत-लाभ विश्लेषण पर अधिक बल दिया।

Y

प्राप्ति (Yield)

इसे एक प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज या लाभांश के रूप में लिया जाता है जो प्रायः वार्षिक आधार पर और निवेश की लागत इसके चालू बाज़ार मूल्य या इसके प्रत्यक्ष मूल्य पर आधारित प्रतिशत के रूप में वर्णित किया जाता है।

परिपक्वता पर प्राप्ति (Yield to Maturity)

बकाया ऋण निर्गमों में प्रतिफल की औसत दर निर्गम की परिपक्वता पर चालू कीमत, ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभ या हानि को विचार में लेता है। इसे बांड या ऋण पर प्रतिफल की आन्तरिक दर के रूप में भी पारिभाषित किया जा सकता है।

Z

शून्य आधारित बजट (Zero based Budget)

बजट बनाने की तकनीक जो गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर परम्परागत तकनीक के अनुसार बजट इस विचार से बनाये जाते हैं कि भावी अवधि की आवश्यकता क्या है भले ही यह बजट गत वर्ष के बजट से ज्यादा या कम क्यों न हो। यह बजट नई

परियोजना के लिए या फिर उसके लिए प्रात्र प्रयुक्त होता है जहां गत वर्ष के आंकड़े संगठन में परिवर्तन के कारण प्रासांगिक नहीं है।

शून्य वृद्धि (Zero Growth)

ऐसी अवस्था जब आर्थिक गतिविधि में कोई वृद्धि न हो जो या तो आर्थिक मंदी के कारण हो या फिर सरकार की यह नीति से कि वृद्धि को रोका जाए।

संदर्भ-सूची
(BIBLIOGRAPHY)

- Government Accounting Board (http://www.gasb.org)
- ONGC (http://www.ongcindia.com/download/Annualreports/ONGC_Annual_Report_10-11.pdf)
- http://indiabudget.nic.in
- http://www.lincolninst.edu/subcenters/teaching-fiscal-dimensions-ofplanning/materials/venkatesh.pdf
- http://www.prlog.org/10975373-important-public-finance-terms.html
- http://grammar.yourdictionary.com/word-lists/government-accountingterms.html
- http://www.economist.com/economics-a-to-z/d
- http://www.nysscpa.org/glossary
- http://www.scottish.parliament.uk/S4_FinanceCommittee/General%20Documents/PublicFinanceGlossary.pdf
- http://economictimes.indiatimes.com
- http://en.wikipedia.org/wiki/Public_finance
- http://books.google.co.in/books?id=ULHK7Y9FdAAC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- http://www.financialmodelingguide.com/financial-modelingtips/tips/banking-financial-terms
- http://www.finance-glossary.com
- http://finmin.nic.in/reports/WhitePaper_BackMoney2012.pdf
- http://www.investorwords.com/641/buyers_market.html
- http://www.investopedia.com/terms/c/capitalgoods.asp#axzz1x5P70jKi
- http://en.wikipedia.org/wiki/Deferred_income

- http://www.businessdictionary.com/definition/governmentsecurities.html
- http://www.theglobaljournals.com
- http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Harrod.html
- http://tribal.nic.in/
- http://www.impactdatasource.com
- http://ccaind.nic.in/
- http://www.cga.nic.in/
- http://portal.indiainfoline.com/
- http://www.theglobaljournals.com
- http://www.economicshelp.org

टिप्पणियां

(NOTES)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....